वर्षः 6 अंकः 13

1-15 जनवरी, 2026 (निःशुल्क)

न्यू इंडिया समाचार

नववर्ष विशेषांक

गुलामी की मानसिकता से मुक्ति भारतीय अस्मिता का पुनर्जागरण

वर्ष 2035 तक 'गुलामी की मानसिकता से मुक्ति' का प्रण बन गई है मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने की संकल्प यात्रा...

ई-कॉपी के लिए QR स्कैन करें

अब दुनियाभर की दीपावली

भारत में व्यापक रूप से मनाई जाने वाली जीवंत परंपराओं में से एक दीपावली को 10 दिसंबर को नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित यूनेस्को अंतर-सरकारी समिति के 20वें सत्र में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया। दीपावली का यूनेस्को सूची में शामिल होना साबित करता है कि हमारी परंपराएं केवल उत्सव नहीं, जीवित सांस्कृतिक ऊर्जा हैं। गरबा, दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, योग... हर उत्सव ने संसार को भारत की आत्मा से परिचित कराया है। भारत उत्सव मनाता है और दुनिया उसमें दिव्यता देखती है। दीपावली का त्योहार 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' के सार्वभौमिक संदेश का प्रतीक है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की भावना को दर्शाता है। साथ ही आशा, नवजीवन तथा सद्भाव का करता है प्रतिनिधित्व...

"भारत और दुनिया भर के लोग रोमांचित हैं। हमारे लिए दीपावली हमारी संस्कृति और लोकाचार से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। यह हमारी सभ्यता की आत्मा है। यह प्रकाश और धार्मिकता का प्रतीक है। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल करने से इस पर्व की वैश्विक लोकप्रियता और भी बढ़ेगी। प्रभु श्रीराम के आदर्श हमारा शाश्वत रूप से मार्गदर्शन करते रहें। **- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

न्यू इंडिया
समाचार

वर्षः 6, अंकः 13 । 1-15 जनवरी, 2026

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा
प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

मुख्य सलाहकार संपादक
संतोष कुमार

वरिष्ठ सहायक सलाहकार संपादक
पवन कुमार

सहायक सलाहकार संपादक
अखिलेश कुमार
चन्दन कुमार चौधरी

भाषा संपादन
सुमित कुमार (अंग्रेजी)
रजनीश मिश्रा (अंग्रेजी)
नदीम अहमद (उर्दू)

सीनियर डिजाइनर
फूलचंद तिवारी

डिजाइनर
अभय गुप्ता
सत्यम सिंह

13 भाषाओं में उपलब्ध न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने के लिए क्लिक करें।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

न्यू इंडिया समाचार के पुराने अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें

https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

न्यू इंडिया समाचार के बारे में लगातार अपडेट के लिए फॉलो करें: @NISPIBIndia

अंदर के पन्नों पर...

आवरण कथा

गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का 10 वर्षीय संकल्प

नववर्ष 2026 के आगाज के साथ ही आइए जानते हैं कि केंद्र सरकार किस तरह गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की दिशा में 10 वर्षीय संकल्प को साकार करने में जुट चुकी है... | 8-27

संसद का शीतसत्र

पीएम मोदी ने लोकतंत्र के मंदिर 'संसद' में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा की शुरुआत की | 30-33

भारत-रूस

विश्वास की विरासत
सहयोग का नया अध्याय

राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुए समझौते | 40-43

समाचार सार | 4-5

व्यक्तित्व : सत्येंद्रनाथ बोस
'बोस-आइंस्टीन सिद्धांत' के प्रणेता | 6

आत्मविश्वासी भारत
एचटी लीडरशिप समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन | 28-29

आलेख : भारत और नेचुरल फार्मिंग...भविष्य की राह!
लिंक्डइन पोस्ट पर पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ाने की अपील की | 34-35

दिव्यांगजनों का समावेशी विकास, राष्ट्र की विकास यात्रा का अभिन्न अंग
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तीकरण पुरस्कार प्रदान किए | 36-37

विशेष रिपोर्ट : भारत में दुनिया का छठा, सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर बेड़ा
परमाणु ऊर्जा का कुल विद्युत उत्पादन में 3% से अधिक का योगदान | 38-39

जनगणना बजट और कोलसेतु नीति को मिली कैबिनेट की मंजूरी
खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रस्तावों को भी दी मंजूरी | 44

विशेष पहल : नया भारत-नई सोच

आपकी पूंजी
आपका अधिकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'आपका पैसा, आपका अधिकार' मानते हुए सोशल मीडिया लिंक्डइन पर विचार साझा किए | 7

प्रकाशक और मुद्रकः कंचन प्रसाद, महानिदेशक, सीबीसी (केंद्रीय संचार ब्यूरो)। **मुद्रणः** जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा. लि., बी-278, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020। **पत्राचार और ईमेल के लिए पताः** कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003। **ईमेलः-** response-nis@pib.gov.in आर. एन. आई. नंबर DELHIN/2020/78812

संपादक की कलम से...

गुलामी की मानसिकता से पूर्ण मुक्ति के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा राष्ट्र

सादर नमस्कार।

सुधी पाठकों, आप सभी को नववर्ष 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष एक नई ऊर्जा लेकर आता है, नया संकल्प लेने का अवसर लेकर आता है। 140 करोड़ नागरिकों के विश्वास के साथ आगे बढ़ रही केंद्र सरकार ने 10 वर्षीय संकल्प लिया है, उसकी सिद्धि में प्रत्येक नागरिक भागीदार बनने को तत्पर है। जन-सहभागिता आज केंद्र सरकार की सभी पहल, सभी नीतियों में सबसे महत्वपूर्ण आधार है। आज भारतवासी महाकवि भरतियार की उस कविता के एक-एक भाव की अनुभूति कर रहा है, जिसका शीर्षक है- "पारुकुलै नल्ल नाडअ-यिंगल, भारत नाड-अ"। महाकवि भरतियार की यह कविता सभी भारतीय को गर्व से भर देने वाली हैं। इस कविता का अर्थ है- ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्न दान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में, वीरता में, सेनाओं के शौर्य में, करुणा में, दूसरों की सेवा में, जीवन के सत्य को खोजने में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है।

आज भारत अपने इसी गौरव का मनोवैज्ञानिक पुनर्जागरण करते हुए विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के साथ अमृत यात्रा की ओर तेजी से अग्रसर है। लेकिन गुलामी की मानसिकता, विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलामी की मानसिकता से पूर्णतया मुक्ति का आह्वान किया है। लाल किले की प्राचीर से 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने पंच प्रण का संकल्प लिया था, जिसमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति महत्वपूर्ण प्रण है। उसी का परिणाम है कि आज हर क्षेत्र में गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर नए गौरव को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अब उसी संकल्प को एक निश्चित लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इस नववर्ष के प्रथम अंक में यही हमारी आवरण कथा बनी है। जिसका एक ही प्रण है- हमें अपने देश को पूरी तरह से, हर क्षेत्र में गुलामी की मानसिकता से पूर्ण रूप से मुक्त करना है।

इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में विज्ञान जगत में अमूल्य योगदान देने वाले सत्येंद्रनाथ बोस, परमाणु ऊर्जा पर विशेष सामग्री, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर संसद में हुई चर्चा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है।

साथ ही, पत्रिका के इनसाइड पेज पर यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में दीपावली को अंकित किए जाने और बैक कवर पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र का स्वामी विवेकानंद को नमन समाहित है।

(धीरेन्द्र ओझा)

हिंदी, अंग्रेजी व अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध पत्रिका पढ़ें/डाउनलोड करें।
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

आपकी बात...

पत्रिका 'भारत ज्ञान' का उत्कृष्ट स्त्रोत

भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाने की परिकल्पना है। ऐसे में विकास के हर क्षेत्र - कृषि, सेवा, उद्योग व रक्षा में मेक इन इंडिया-मेक फॉर इंडिया, वोकल फोर लोकल, पीएलआई योजना पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य बहुआयामी विकास योजनाओं के माध्यम से भारत के 4 अंग - किसान, नारी, युवा व गरीब आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर हैं। न्यू इंडिया समाचार पत्रिका 'भारत ज्ञान' का उत्कृष्ट स्त्रोत है।

hanwantsinghrathore0@gmail.com

विभिन्न सरकारी विभागों की परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी

मैं न्यू इंडिया समाचार जैसे बहुमूल्य पब्लिकेशन को पाने और पढ़ने के लिए हमेशा उत्सुक रहता हूं। इस पत्रिका में देश की पहल और उपलब्धियों को दर्शाया जाता है। यह एक उत्कृष्ट पत्रिका है। इससे मुझे विभिन्न सरकारी विभागों की परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिल रही है। न्यू इंडिया समाचार के माध्यम से हम देश के विकास की एक नई दिशा देख पा रहे हैं।

kisanmorcha.gs@gmail.com

डेवलपमेंट प्रोग्राम और एक्टिविटी से आ रही जागरूकता

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका के माध्यम से उन लोगों तक सूचना पहुंच रही है जिन तक ऐसी जानकारी नहीं पहुंच पाती थी। मुझे यह जानकार खुशी हुई कि बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम और एक्टिविटी से वे जागरूक हो रहे हैं। अपने अधिकारों के बारे में जान रहे हैं। वेलफेयर और सर्विस ऑफिस के स्टाफ इस बात पर दुख जताते हैं कि टारगेट ग्रुप प्रोग्राम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ऐसे में अगर वे आपके पास नहीं आ पाते हैं, तो हमें उनके पास जाना चाहिए। हमारी सरकार ने भारत के गौरव यानी आदिवासियों, जिनके बलिदानों को कभी याद नहीं किया जाता, उनके उत्थान की पूरी कोशिश की है।

पी. प्रेमा, तंजावुर

prof.prema@gmail.com

योजनाओं से अपडेट रखने में अहम भूमिका

न्यू इंडिया समाचार का ताजा संस्करण मिला। इस पत्रिका ने देश में चल रही अलग-अलग योजनाओं और घटनाओं के बारे में मुझे अपडेट रखने में अहम भूमिका निभाई है। विकसित भारत से लेकर आदिवासी विकास, किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाने से लेकर आजादी की लड़ाई के नायकों को याद करने तक, यह पत्रिका समाज के अलग-अलग तबकों से जुड़े कई विषयों पर काम की जानकारी देती है। मैं भविष्य के संस्करणों को पढ़ने के लिए उत्साहित रहता हूं।

सौरव शर्मा

sharmasourav1261@gmail.com

पत्राचार और ईमेल के लिए पता: कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003.
ईमेल- response-nis@pib.gov.in

न्यू इंडिया समाचार को आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर शनिवार-रविवार को दोपहर 3:10 से 3:25 बजे तक सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

समाचार सार

मेरा गांव मेरी धरोहर...

6.38 लाख गांव का सांस्कृतिक मानचित्रण पूरा

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में सांस्कृतिक मानचित्रण के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर (एमजीएमडी) कार्यक्रम के तहत 6,38,365 गांवों की पहचान की है। जिनमें से अब तक 6,23,449 गांवों का डेटा एमजीएमडी पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है जिसमें इन गांव की सांस्कृतिक पहचान को दर्ज की जा रही है। इस डॉक्युमेंटेशन में मूर्त और अमूर्त दोनों तरह की सांस्कृतिक विरासत जैसे लोक परंपराएं, मान्यताएं, रीति-रिवाज, ऐतिहासिक महत्व, कला रूप, सांस्कृतिक धरोहर स्थल, पारंपरिक भोजन, प्रसिद्ध कलाकार, मेले-त्योहार, पारंपरिक पोशाक, आभूषण और स्थानीय पहचान वाले स्थल शामिल हैं। यह कार्यक्रम न केवल ग्रामीण पहचान को मजबूत बनाता है बल्कि इससे प्रत्येक गांव का एक प्रमाणिक सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार होता है।

लद्दाख से जुड़ी 125 सीमावर्ती बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की 125 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं 7 दिसंबर को राष्ट्र को समर्पित की गई। यह लद्दाख से एक साथ उद्घाटन की गई अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। 5,000 करोड़ रुपये की लागत से 2 केंद्र शासित प्रदेशों और 7 राज्यों में फैली 28 सड़कें, 93 पुल और 4 विविध परियोजनाएं पूरी हुईं जो बीआरओ के इतिहास में सबसे अधिक मूल्य की उद्घाटन परियोजनाएं हैं। इसमें शामिल लद्दाख की दारबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी सड़क पर स्थित रणनीतिक श्योक सुरंग से दूरदराज के गांवों और आगे के सैन्य स्थानों के लिए अंतिम चरण तक की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

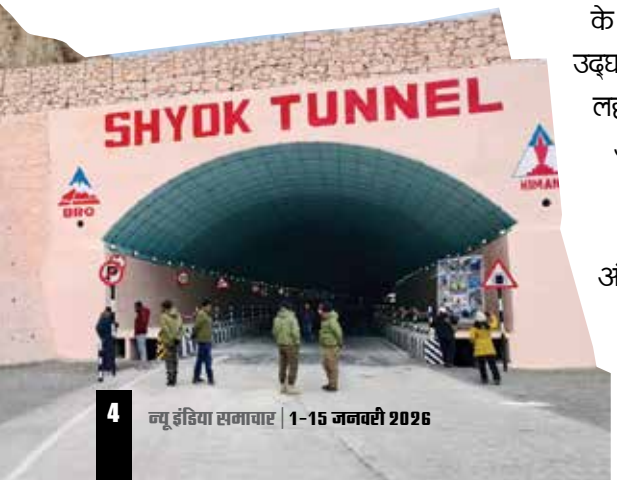

वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को लोअर बर्थ

भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों सहित अन्य यात्रियों की सुविधा के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी प्रयास के तहत भारतीय रेल में वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को लोअर बर्थ मिलेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि उपलब्धता के अनुसार, भले ही विकल्प न दिया गया हो लेकिन वरिष्ठ नागरिकों तथा 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को स्वतः रूप से निचली बर्थ आवंटित की जाएगी। इतना ही नहीं, वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्लीपर में 6-7 निचली बर्थ, थर्ड एसी में 4-5 और सेकंड एसी में 3-4 बर्थ निर्धारित है। साथ ही, लगभग सभी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में दिव्यांगजन के लिए एक अलग कोच की व्यवस्था की गई है।

सामाजिक सुरक्षा

अटल पेंशन योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना में लगातार बढ़ रहे लाभार्थी

सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने वाली केंद्र सरकार की योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई जिसमें अक्टूबर 2025 तक 8,34,13,738 लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं जिसमें करीब 48 फीसदी महिलाएं हैं। यह योजना 18-40 वर्ष की आयु के उन सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिनका बैंक या डाकघर में बचत खाता हो। योजना के अनुसार लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन मिलेगी। 2035 से पेंशन का लाभ मिलना शुरू होगा। वहीं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में 1 दिसंबर 2025 तक 30 लाख लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं जिनमें से 23.09 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। योजना 17 सितंबर, 2023 को शुरू की गई थी। इस योजना के लाभार्थियों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ओएनडीसी, फैबइंडिया, मीशो आदि जैसे विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से ऑनलाइन मार्केटिंग सहायता प्रदान की जा रही है।

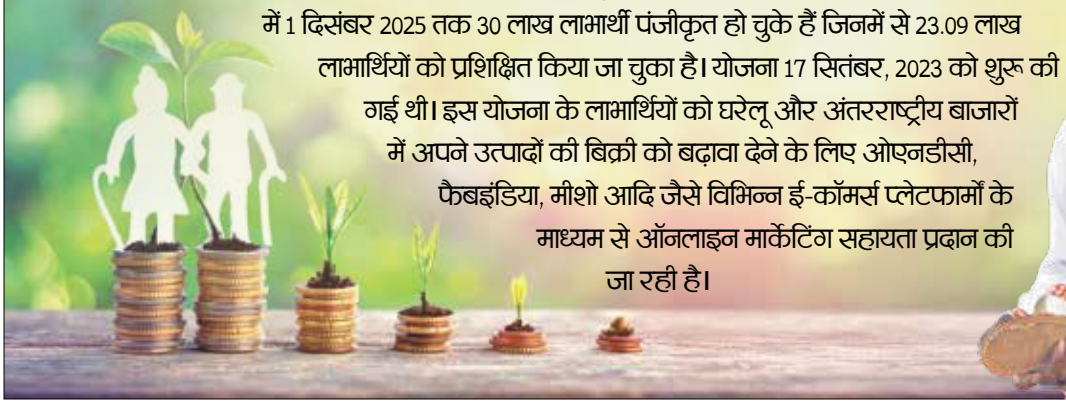

जल आपूर्ति डेटा की जानकारी के लिए 'सुजलाम भारत' एप की शुरुआत

ग्रामीण पेयजल शासन को डिजिटल, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'सुजलाम भारत' एप की शुरुआत की गई है। सुजलाम भारत- 'सुजल गांव **ID**' के माध्यम से देश की सभी ग्रामीण जल योजनाएं एक राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री से एकीकृत होंगी, जिससे स्रोत से लेकर नल तक पूरी जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध होगी। यह एप परिसंपत्तियों, ऑपरेशन और मेंटेनेंस, सेवा-प्रदर्शन और रखरखाव की विश्वसनीय एवं वास्तविक-समय में डिजिटल निगरानी को सुदृढ़ करेगा।

भविष्य को ट्रांसफॉर्म करेगी
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने ऊर्जा सुरक्षा के अभियान में देश के लोगों को सीधी भागीदारी करने का मौका दे दिया है। केंद्र सरकार इस योजना में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के लिए जागरूकता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर लगातार काम कर रही है। यही वजह है कि वित्त वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर प्रणाली की स्थापना के लक्ष्य के मुकाबले कुल 23,96,497 घरों में रूफटॉप सौर प्रणाली स्थापित भी की जा चुकी है। यह लक्ष्य का करीब-करीब एक चौथाई है। इतना ही नहीं योजना में 3 दिसंबर, 2025 तक 53,54,099 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

दिसंबर, 2025 में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज भारत हर साल करीब-करीब 125 लाख करोड़ रुपये के पेट्रोल-डीजल-गैस का आयात करता है। देश पर सूर्य भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, लेकिन 2014 तक भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सिर्फ 3 गीगावॉट थी। बीते 10 वर्षों में अब ये बढ़कर 130 गीगावॉट के आसपास पहुंच चुकी है। इसमें भी 22 गीगावाट ऊर्जा क्षमता सिर्फ रूफटॉप सोलर से जोड़ी गई है। ■

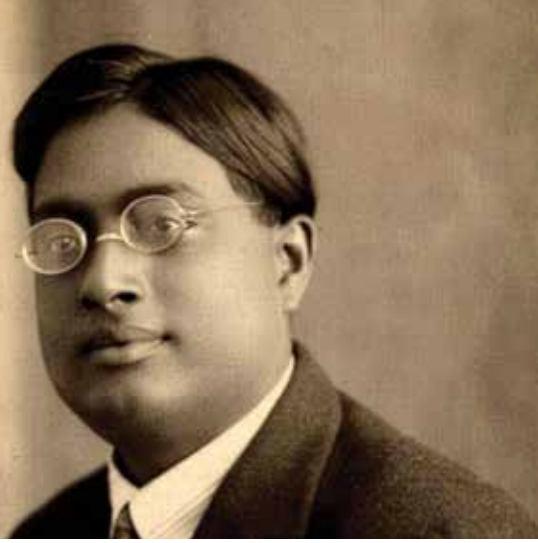

'बोस-आइंस्टीन सिद्धांत' के प्रणेता

जन्म : 1 जनवरी 1894 ■ मृत्यु : 4 फरवरी 1974

ज्ञान जगत में अमूल्य योगदान देने वाले सत्येंद्रनाथ बोस ने प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिल कर 'बोस-आइंस्टीन सिद्धांत' की खोज कर भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भारत का परचम लहराया। उन्होंने न केवल भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया बल्कि इसे एक नई दिशा देकर पूरे विश्व में भारत को विशेष स्थान दिलाने का काम किया। आधुनिक भौतिक विज्ञान को नई दिशा प्रदान करने में दिया गया उनका अतुलनीय योगदान युगों-युगों तक रहेगा अविस्मरणीय...

कोलकाता में 1 जनवरी 1894 को जन्मे सत्येंद्रनाथ बोस पढ़ाई के मामले में बचपन से ही मेधावी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे परीक्षाओं में सर्वाधिक अंकों के साथ उर्तीण होते रहे। सत्येंद्रनाथ के पिता सुरेंद्रनाथ बोस ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे। सत्येंद्रनाथ उनके 7 बच्चों में सबसे बड़े थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई नादिया जिले के बाड़ा जगुलिया गांव में हुई। बाद में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेजिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया जहां जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र रे जैसे विद्वानों के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की। फिर वह उसी कॉलेज में फिजिक्स के प्राध्यापक के तौर पर जुड़ गए और 1921 में नई स्थापित ढाका यूनिवर्सिटी में भौतिकी विभाग में रीडर के तौर पर कार्य करने लगे। बाद में वह यूरोप चले गए और फिर स्वदेश लौट आए थे।

सत्येंद्रनाथ बोस ऐसे विद्वान थे जो खुद से सीखते थे। औपचारिक रिसर्च शिक्षा की कमी और वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय से कम जुड़ाव के बावजूद वे सफल हुए। उनका मौलिक शोधपत्र 1924 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा जर्मन में अनुवादित होने के बाद प्रकाशित हुआ। अज्ञात विज्ञान के प्रति एकनिष्ठ समर्पण से उन्होंने 1924 में नया रास्ता दिखाने वाला काम किया। उन्होंने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की नींव रखी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का आधार बनाया। सत्येंद्रनाथ बोस ने ही छोटे से छोटे कणों की अवधारणा को माना था इसी आधार पर इन्हें बोसोन्स का नाम दिया गया। आइंस्टीन के बायोग्राफर अब्राहम पेस ने उनके काम को पुरानी क्वांटम थ्योरी पर आखिरी चार क्रांतिकारी पेपर्स में से एक माना है। सत्येंद्रनाथ बोस का नाम साइंस के इतिहास में बोस स्टैटिस्टिक्स, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन और हिग्स बोसोन्स जैसे कॉन्सेप्ट्स और शब्दों से अमर हो गया। बोस के योगदान ने फिजिक्स की दुनिया में लोगों की समझ को मौलिक रूप से बदल दिया और कई वैज्ञानिक सफलताओं का मार्ग प्रशस्त किया।

उनकी वैज्ञानिक गहराई का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि बाद में उनके आइडियाज को अलग-अलग फिजिकल एप्लीकेशन्स में आगे बढ़ाने वाले शोधकर्ताओं को फिजिक्स में कई नोबेल पुरस्कार दिए गए। प्रो. बोस लोकल भाषा में साइंस पढ़ाने के पैरोकार थे। उन्होंने बंगाली साइंस मैगजीन ज्ञान-ओ-बिग्यान शुरू की थी। 1954 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर बोस के कार्यों को सम्मानित करने के लिए 1986 में भारत सरकार ने कोलकाता में अनुसंधान संस्थान, एस. एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज स्थापित किया। 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी केंद्र में एस. एन. बोस भवन का उद्घाटन किया गया था।

1 जनवरी 2018 को प्रो. सत्येंद्रनाथ बोस की 125वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैंने उनकी कामयाबियों के बारे में बहुत कुछ जाना है जो उनके समय और समाज से बहुत आगे थीं। बहुत कम संसाधन और बहुत ज्यादा संघर्ष के बीच उन्होंने अपने विचारों-अविष्कारों से लोगों की सेवा की। आज भी हम उनकी प्रतिबद्धता और रचनात्मकता से सीख रहे हैं। पीएम मोदी ने आह्वान किया था कि अगर हर वैज्ञानिक सिर्फ एक बच्चे की साइंस की पढ़ाई, रिसर्च के प्रति उसका रुझान बढ़ाने के लिए अपना थोड़ा समय देने लगे तो देश में लाखों छात्रों का भविष्य बन सकता है। आचार्य सत्येंद्रनाथ बोस के 125वीं जन्म वर्ष में यह उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। 4 फरवरी 1974 को बोस का निधन हो गया। ■

आपकी पूंजी आपका अधिकार

सरकार और जनता के बीच जब विश्वास मजबूत होता है, तो राष्ट्र की प्रगति नई ऊंचाई को छूती है। बीते 11 वर्षों में सरकार और जनता के बीच भरोसे का ही परिणाम है कि भारत अपनी विकास यात्रा में नित नए अध्याय लिख रहा है। इसी कड़ी में अब गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति के लक्ष्य के साथ बैंक, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी के पास बिना किसी दावे के पड़े करोड़ों रुपये हकदारों को ढूंढकर लौटाने की हो चुकी है शुरुआत। नए भारत की इस सोच को साकार करने वाली पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'आपका पैसा, आपका अधिकार' मानते हुए सोशल मीडिया लिंक्डइन पर विचार किए साझा...

नागरिकों के अनक्लेम्ड पड़े हैं...

भारतीय बैंकों में	बीमा कंपनियों में
78,000 करोड़ रुपये	**14,000** करोड़ रुपये

म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास लगभग 3,000 करोड़ रुपये हैं और 9,000 करोड़ रुपये के डिविडेंड भी अनक्लेम्ड पड़े हैं।

कुछ दिन पहले 'हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट' में अपनी स्पीच के दौरान, मैंने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े रखे थे...

- इन बातों ने बहुत से लोगों को चौंका दिया है।
- आखिरकार, ये एसेट्स अनगिनत परिवारों की मेहनत से बचाई गई सेविंग और इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं।
- अक्टूबर 2025 में आपकी पूंजी, आपका अधिकार - **Your Money, Your Right** पहल शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक अपने अधिकार के अनुसार अपना हक वापस पा सके।

फंड को ट्रैक करने और क्लेम करने की प्रक्रिया को आसान व पारदर्शी बनाने के लिए, डेडिकेटेड पोर्टल भी बनाए गए हैं। जो इस प्रकार हैं:

- भारतीय रिजर्व बैंक (**RBI**) – **UDGAM** पोर्टल **https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits/#/login** अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट & बैलेंस
- भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (**IRDAI**) - बीमा भरोसा पोर्टल: **https://bimabharosa.irdai.gov.in/Home/UnclaimedAmount** अनक्लेम्ड इंश्योरेंस पॉलिसी रकम
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**SEBI**) - **MITRA** पोर्टल: **https://app.mfcentral.com/links/inactive-folios** म्यूचुअल फंड में अनक्लेम्ड रकम
- कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, **IEPFA** पोर्टल:**https://www.iepf.gov.in/content/iepf/global/master/Home/Home.html** अनपेड डिविडेंड & अनक्लेम्ड शेयर

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिसंबर 2025 तक, पूरे ग्रामीण और शहरी भारत के 477 जिलों में फैसिलिटेशन कैंप लगाए गए हैं। हमारा जोर दूर-दराज के इलाकों को कवर करने पर रहा है।

- सरकार, नियामक संस्थाओं, बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों सहित सभी हितधारकों की संयुक्त कोशिशों के माध्यम से करीब 2,000 करोड़ रुपये पहले ही वास्तविक हकदारों को वापस मिल चुके हैं।

लेकिन हम आने वाले दिनों में इस अभियान को और बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए, मैं आपसे इन बातों पर मदद का अनुरोध करता हूं...

- क्या आपके परिवार के पास कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट, बीमा रकम, डिविडेंड या निवेश हैं।
- ऊपर बताए गए पोर्टलों पर जाएं।
- अपने जिले में सुविधा कैंप का लाभ उठाएं।
- जो आपका है, उसे क्लेम करने के लिए अभी कदम बढ़ाएं। एक भूली हुई फाइनेंशियल संपत्ति को नए अवसर में बदलें। आपका पैसा आपका है। आइए, यह सुनिश्चित करें कि यह आपको वापस मिले।

आइए, साथ मिलकर एक पारदर्शी, आर्थिक रूप से सशक्त और समावेशी भारत बनाएं!

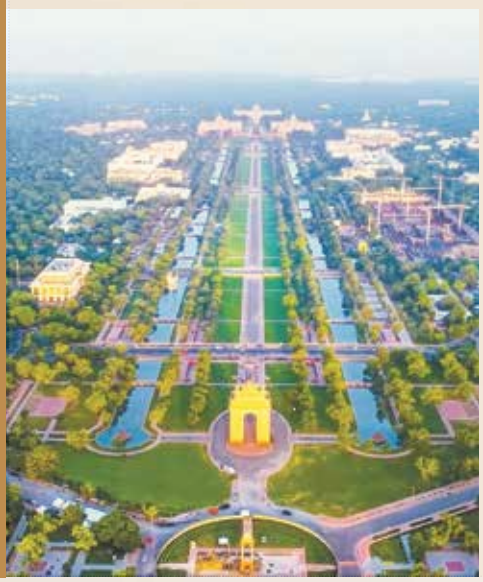

गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का

10 वर्षीय संकल्प

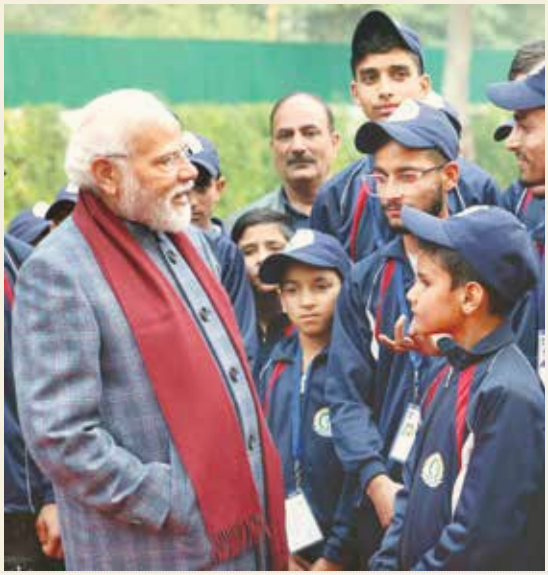

गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का प्रण भारतीय अस्मिता का पुनर्जागरण है, स्वाभिमानी सभ्यता का पुनः उद्घोष है। जब कोई राष्ट्र अपनी पहचान को भूलता है, तो स्वयं को खो देता है लेकिन जब पहचान लौटती है, तो राष्ट्र का आत्मविश्वास भी लौट आता है। बीते कुछ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा गुलामी के प्रतीकों और उससे जुड़ी नीतियों को मिटाने के लिए उठाए गए कदमों से देश ने स्वतंत्र होने के अभिमान के साथ तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। देश का विचार और देश का व्यवहार, दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं लेकिन यह न शुरुआत है, न अंत है। यह मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक, बन गई है निरंतर चलने वाली विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की यात्रा...

नववर्ष 2026 के आगाज के साथ ही आइए जानते हैं कि केंद्र सरकार किस तरह गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की दिशा में 10 वर्षीय संकल्प को साकार करने में जुट चुकी है

नववर्ष 2026 एक नया संकल्प और उसकी सिद्धि का लक्ष्य लेकर आया है। अक्सर, कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। एक ऐसा हिस्सा जो भले देखने-सुनने में बड़ा न लगता हो, लेकिन वह हमारे अवचेतन मन में बड़े बदलाव लेकर आता है। ठीक उसी तरह जैसे आजादी के आंदोलन के समय चरखा और एक मुट्ठी नमक जैसे छोटे प्रतीकात्मक प्रयासों ने सामाजिक एकता का ऐसा ताना-बाना बुना जिसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। इतिहास साक्षी है कि खादी का एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया और उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। ठीक उसी तरह अब, जब एक राष्ट्र के रूप में भारत स्वयं को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है तो गुलामी के प्रतीकों को मिटाना भी राष्ट्र का कर्तव्य बन जाता है।

इसी सोच को साकार करने के लिए नया भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कार्यशैली और नीतियों से गुलामी के प्रतीकों को मिटाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आज का नया भारत, बहुत तेजी से बदल रहा है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और सबका प्रयास के संबंध में विस्तार से चर्चा की थी। उस पथ पर आगे बढ़ते भारत ने, गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर अब स्वतंत्र होने के स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। कोई भी देश, जब ऐसा ठान लेता है, तो उसका कायाकल्प होना शुरू हो जाता है। ऐसे में देश को आगे बढ़ना है, तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू है- गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति। बीते कुछ वर्षों में हुई पहल का ही परिणाम है कि राष्ट्रीय प्रतीकों में औपनिवेशिक और गुलामी के प्रतीकों की छाया कम हुई है। ज्ञान और संस्कृति में

आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश ने अपने लिए 'पंच प्रण' का विजन रखा है। इनमें विकास के बड़े लक्ष्यों का संकल्प है, कर्तव्यों की प्रेरणा है। गुलामी की मानसिकता के त्याग का आवाहन और अपनी विरासत पर गर्व का बोध है। आज भारत के आदर्श, आयाम, संकल्प, लक्ष्य, पथ और प्रतीक अपने हैं।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री मोदी ने पंच प्रण का आह्वान 15 अगस्त, 2022 को लाल किले की प्राचीर से किया था।

गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की दिशा में राष्ट्र के कदम...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'पंच प्रण' के आह्वान के प्रति 140 करोड़ नागरिकों ने लिया है प्रण, ताकि 2047 के स्वर्णिम भारत का सपना हो साकार...

पहला

विकसित भारत, उससे कम कुछ नहीं।

दूसरा

गुलामी की मानसिकता का पूरी तरह त्याग।

तीसरा

अपनी विरासत पर गर्व करना।

चौथा

राष्ट्र की एकता बढ़ाने का पुरजोर प्रयास करना।

पांचवा

हर नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करे।

भारतीय दृष्टिकोण मजबूत हुआ है। भारतीयता के भाव और विचार से ओतप्रोत आज भारत अभूतपूर्व विकास, सुशासन और सांस्कृतिक-आध्यात्मिक पुनर्जागरण की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी प्रेरणामयी धारा में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए कुछ महत्वपूर्ण नामकरण जो इस प्रकार हैं- प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ, राजभवन को लोकभवन, राजनिवास को लोक निवास तथा केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन, भारतीय शासन-दर्शन को एक नवीन अर्थपूर्ण और गरिमामय स्वरूप प्रदान करते हैं। यह नूतन नामकरण सत्ता के वैभव का नहीं, बल्कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की सोच, जनसेवा, लोकसंपर्क और कर्तव्यनिष्ठा के शाश्वत मूल्यों को प्रतिष्ठित करते हैं। बीते 11 वर्षों के सेवाकाल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने शासन को सत्ता नहीं, अपितु सेवा के अनवरत व्रत के रूप में आत्मसात किया है। प्रधानसेवक भाव से प्रेरित यह दूरदर्शी पहल विकसित भारत के स्वर्णिम संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण, अनुकरणीय और इतिहास-निर्माणकारी आयाम है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारतीयता के भाव से भरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र से आह्वान किया है कि मैकाले ने भारत को जिस गुलामी की मानसिकता से भर दिया है, उस सोच से अगले 10 साल में यानी 2035 तक मुक्ति पाकर रहेंगे।

मैकाले मानसिकता से मुक्ति का लक्ष्य 2035...

190 साल पहले, 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को उसकी जड़ों से उखाड़ने के अभियान की शुरुआत की थ। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। दस साल बाद, यानी 2035 में उस अपवित्र घटना के 200 वर्ष पूरे होंगे।

प्रतीकात्मक नाम परिवर्तन

यह बदलाव केवल साइन बोर्ड बदलने जैसा नहीं है। प्रतीक हमारे अवचेतन मन पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं। गुलामी के प्रतीकों का हटना उस मानसिकता को तोड़ने की पहली सीढ़ी है क्योंकि प्रतीकों से समाज कई अर्थ ग्रहण करता है...

- **सेवा तीर्थ** : वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ किया गया।
- **लोक भवन और लोक निवास** : देश के राजभवन को लोक भवन और राजनिवास को लोक निवास का नाम दिया गया।
- **लोक कल्याण** : वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास के नजदीक वाली सड़क को रेस कोर्स रोड कहा जाता था, जिसका नाम लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। रेस कोर्स नाम अंग्रेजों का दिया हुआ था।
- **एपीजे अब्दुल कलाम रोड** : वर्ष 2015 में दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया गया।
- **दारा शिकोह रोड** : वर्ष 2017 में डलहौजी रोड का नाम बदल कर यह नाम दिया गया।

- **अमृत उद्यान** : स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के समारोह के अवसर पर 'आजादी का अमृत महोत्सव' के रूप में राष्ट्रपति भवन उद्यानों को 'अमृत उद्यान' नाम दिया गया।
- **तीन मूर्ति हाइफा** : वर्ष 2018 में तीन मूर्ति चौक का नाम बदल कर तीन मूर्ति हाइफा चौक किया गया।
- पिछले कुछ सालों में ऐसे कई नाम बदले गए हैं और बदलने की प्रक्रिया चल रही है। इन स्थानों पर अब औपनिवेशिक नाम हटाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों या भारतीय पहचान वाले नाम दिए जा रहे हैं।

जनमानस पर प्रभाव

औपनिवेशिक काल में दिए गए नाम भारत की गुलामी की पहचान को दर्शाते थे। उसे अब कर्तव्य, जन भावना और भारतीय गौरव से परिपूर्ण नाम देने से मानसिक स्वतंत्रता की भावना को बल मिलता है। कर्तव्य पथ जैसे नाम जनता को उत्तरदायित्व, सेवा-कर्तव्य की ओर प्रेरित करते हैं।

इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्पित आह्वान किया है कि आने वाले दस वर्षों में भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के संकल्प की सिद्धि की ओर बढ़ने से पहले इसका इतिहास भी समझना होगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से भी पहले, वो साल था 1835 का, जब ब्रिटिश सांसद थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था। उसने ऐलान किया था, मैं ऐसे भारतीय बनाऊंगा कि वो दिखने में तो भारतीय होंगे लेकिन मन से अंग्रेज होंगे। इसके लिए मैकाले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं, बल्कि उसका समूल नाश कर दिया। खुद महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था एक सुंदर वृक्ष थी, जिसे जड़ से हटा कर नष्ट कर दिया गया।

भारत की शिक्षा व्यवस्था में अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाया जाता था, भारत की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाई के साथ कौशल पर भी उतना ही जोर था, इसलिए मैकाले ने भारत की

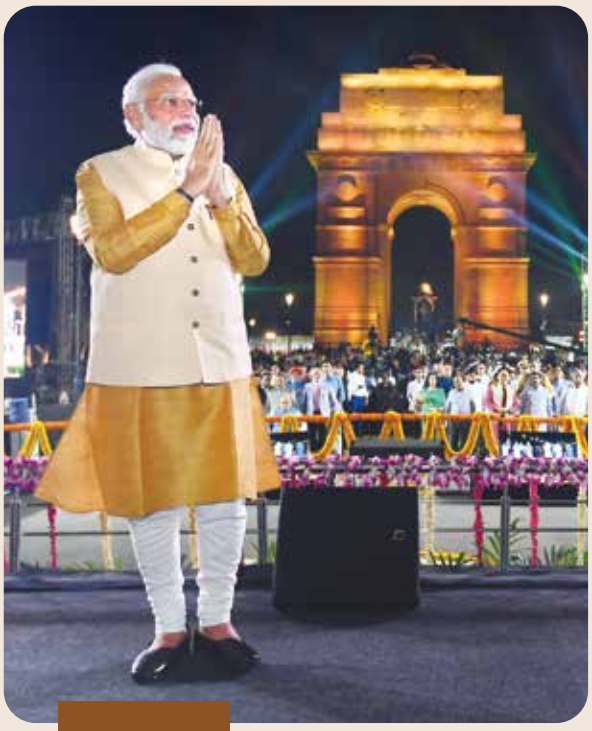

कर्तव्य पथ

वर्ष 2022 में ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। सबसे पहले इसका नाम किंग्सवे था। यह नाम 1911 में दिया गया था। तब दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे।

- **द्वीपों के नाम बदले :** नेताजी की अंडमान निकोबार द्वीप की ऐतिहासिक यात्रा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंडमान स्थित हैवलॉक द्वीप को स्वराज, नील द्वीप को शहीद द्वीप और रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम दिया।

शिक्षा व्यवस्था की कमर तोड़ने की ठानी और उसमें सफल भी रहा। मैकाले ने यह सुनिश्चित किया कि उस दौर में ब्रिटिश भाषा, ब्रिटिश सोच को ज्यादा मान्यता मिले और इसका खामियाजा भारत ने आने वाली सदियों में उठाया। मैकाले ने लोगों के आत्मविश्वास को तोड़ दिया, लोगों के भीतर हीन भावना का संचार किया। मैकाले ने एक झटके में हजारों वर्षों के भारतीय ज्ञान-विज्ञान, कला-संस्कृति, यानी पूरी जीवन शैली को ही ध्वस्त करने की कोशिश की। वहीं पर बीज पड़ा कि भारतीयों को अगर आगे बढ़ना

> *हमें देश को पूरी तरह से गुलामी की मानसिकता से मुक्त करना है। 140 करोड़ देशवसियों की मदद के बिना ये मैं कर नहीं पाऊंगा। मैकाले की जिस नीति ने भारत में मानसिक गुलामी के बीज बोए थे, उसको 2035 में 200 साल पूरे हो रहे हैं। इन्हीं दस वर्षों में हम सभी को मिलकर, देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहना है।*
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

है, अगर कुछ बड़ा करना है, तो उसे विदेशी तौर तरीकों से ही करना होगा। यह भाव आजादी मिलने के बाद और भी पुख्ता हुआ। भारत की शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज की आकांक्षा, सभी कुछ विदेशों से जुड़ गई। अपनी चीजों पर गौरव करने का भाव कम होता गया। गांधी जी ने जिस स्वदेशी को आजादी का आधार बनाया था, उसको पूछने वाला ही कोई नहीं रहा। गवर्नेंस का मॉडल भी विदेश में खोजने लगे। इनोवेशन के लिए विदेश की तरफ देखने लगे। यही मानसिकता रही, जिसकी वजह से आयातित विचार, आयातित सामान और सेवाएं, सभी को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति समाज में स्थापित हो गई। मैकाले ने जो कुछ सोचा था, उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। भारत को आजादी तो मिली, लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है और जो अपनी चीजें हैं, उनमें खोट ही खोट है।

इसी सोच को जड़ से खत्म करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई पर विशेष बल दिया गया। मैकाले की दी शिक्षा पद्धति पर सवाल तो न जाने कितने मंच और भाषणों में उठाए गए, लेकिन इसे बदलने का साहस प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया। देश में 34 वर्ष बाद 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई जो पूरी तरह से व्यावहारिकता

भारतीय नौसेना ने भी गुलामी के निशान को उतारकर, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक को धारण कर लिया है। नेशनल वॉर मेमोरियल बनाकर देश ने, समस्त देशवासियों की बरसों पुरानी इच्छा को भी पूरा किया है।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

और कौशल आधारित है। जब अंग्रेजी ने हमारी पूरी व्यवस्था को जकड़ लिया है, ऐसे में सरकार ने मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा को महत्व दिया। आज हिंदी को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्थान मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ आर्थिक मंचों को छोड़कर अधिकांशतः वैश्विक मंचों पर मातृभाषा में ही बोलने को प्राथमिकता देते हैं। सही अर्थों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए अब विदेशी भाषा की मजबूरी से भी देश के युवाओं को आजादी मिली है। यानी, आज देश का विचार और देश का व्यवहार दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं। यह मुक्ति ही राष्ट्र को विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब हम अपने देश को सम्मान नहीं देते हैं, स्वदेशी इकोसिस्टम को नकारते हैं, मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को नकारते हैं तो गुलामी की मानसिकता हावी होती है। ऐसे ही स्थानीय भाषाओं की बात है। जापान, चीन और कोरिया जैसे देश, जिन्होंने पश्चिम के अनेक तौर-तरीके अपनाए, लेकिन अपनी भाषा पर समझौता नहीं किया। इसलिए, भारत ने भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई पर विशेष बल दिया। भारत का स्पष्ट मत है कि अंग्रेजी से विरोध नहीं, लेकिन भारतीय भाषाओं का समर्थन और उसे श्रेष्ठता के भाव से आगे बढ़ाना है।

नए पहचान चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक से राष्ट्र की नई कार्य संस्कृति का विस्तार

नए पहचान चिन्ह और राष्ट्रीय प्रतीक देश की आधुनिक सोच और बदलती कार्य-संस्कृति का प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। ये न केवल राष्ट्र की नई दिशा को परिभाषित करते हैं, बल्कि एक सशक्त, दक्ष और प्रगतिशील भारत की भावना को भी बढ़ाते हैं आगे...

- **नौसेना का नया ध्वज** : भारतीय प्रतीकों पर आधारित छत्रपति शिवाजी की शाही मुहर से प्रेरित चिन्ह नौसेना के ध्वज पर लगाया गया। ध्वज में लाल रंग के सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाया।

राष्ट्र के लिए निर्णायक बन रहा 'कर्तव्य' का उद्घोष

राजधानी दिल्ली में ही कर्तव्य पथ, देश का नया संसद भवन, नया रक्षा भवन, भारत मंडपम्, यशोभूमि, शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा और कर्तव्य भवन। यह केवल कुछ नए भवन और सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं, अमृत काल में इन्हीं भवनों में विकसित भारत की नीतियां बनेंगी, विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय होने लगे हैं, आने वाले दशकों में यहीं से राष्ट्र की दिशा तय होगी। राजपथ को

- **आम बजट के समय में बदलाव** : अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में बजट के समय को बदला गया। वर्ष 2001 से दिन में 11 बजे बजट पेश होने लगा। वर्ष 2000 तक आम बजट शाम पांच बजे पेश किया जाता था।
- **बजट की तारीख भी बदली** : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो कदम आगे बढ़ते हुए आम बजट की तारीख को 28 फरवरी की जगह 1 फरवरी किया। यही नहीं 92 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए रेल बजट का आम बजट के साथ विलय कर दिया गया।
- **लाल बत्ती कल्चर खत्म** : सेंट्रल मोटर वाहन एक्ट 1989 में संशोधन कर केंद्र सरकार ने देश में लाल बत्ती कल्चर को खत्म कर दिया। केवल जरूरी सेवा वाहनों पर बत्ती लगाने की अनुमति दी गई है। अंग्रेजी कालखंड की लाल बत्ती संस्कृति को पूरी तरह से खत्म किया गया।

राष्ट्रीय समर स्मारक

शहीदों के लिए विशिष्ट स्मारक के रूप में राष्ट्रीय समर स्मारक को स्वीकार किया गया। अमर जवान ज्योति की लौ का भी यहीं विलय कर दिया गया।

- **दरबार प्रथा का अंत** जम्मू-कश्मीर में जुड़वा राजधानी श्रीनगर और जम्मू के बीच 149 साल से चल रही 'दरबार मूव' प्रथा जून 2021 में खत्म कर दी गई। इस प्रथा के खत्म होने से सालाना करीब 200 करोड़ रुपये की बचत हुई।
- **1862 से चल रही थी परंपरा** : राजधानी बदलने की परंपरा वर्ष 1862 में डोगरा शासक गुलाब सिंह ने शुरू की थी। गुलाब सिंह महाराजा हरि सिंह के पूर्वज थे। हरि सिंह के समय ही जम्मू-कश्मीर भारत का अंग बना था।

जनमानस पर प्रभाव

प्रतीक और नाम हमारी सोच में गहराई से असर डालते हैं। जब प्रतीक बदलते हैं, मानसिकता बदलने का अवसर मिलता है और गुलामी की भावना की जगह राष्ट्रीय आत्म गौरव की भावना बढ़ती है।

कर्तव्य पथ का नाम और अब वहां कॉमन सेंट्रल सेक्ट्रेरिएट को कर्तव्य भवन का नाम दिया गया है। कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन, यह नाम लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना का उद्घोष करते हैं। कर्तव्य पथ पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले इसका नाम था, किंग्सवे। यह नाम इसे 1911 में मिला था। तब दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे। ये वही समय था जब कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत (ब्रिटिश शासन) की राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। इसलिए अंग्रेजों ने किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में इस जगह का नाम किंग्सवे रखा था। 1955 में इसका नाम बदलकर राजपथ किया गया। जो एक तरह से किंग्सवे का ही हिंदी अनुवाद था। अब कर्तव्य पथ होने से यह औपनिवेशिक काल की गुलामी के प्रतीक से मुक्ति की तरह है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू नए रूप में जनता के स्वागत के लिए तैयार है। इस पूरे प्रोजेक्ट की घोषणा सितंबर 2019 में हुई थी। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। इसी के एक अंग के रूप में

विकसित भारत की नीतियों की साक्षी बनती भव्य इमारतें

अमृत काल में उभरती भव्य इमारत विकसित भारत की प्रगतिशील सोच और दूरदर्शी नीति की साक्षी बन रही हैं। यह न केवल भारत की तकनीकी क्षमता दर्शाती हैं, बल्कि आत्मनिर्भर-उन्नत राष्ट्र के संकल्प को भी करती हैं मजबूत...

- **सेंट्रल विस्टा** : केवल वास्तु, पर्यटन नहीं, बल्कि नई पहचान बनाने की पहल, जहां ब्रिटिश दौर की आलीशान सत्ता संरचना से इतर लोक-भाव व नागरिक उपयोग से जुड़ाव हो। इस प्रोजेक्ट की घोषणा सितंबर 2019 में हुई थी।
- पीएम मोदी ने 10 सितंबर 2020 को इस परियोजना की आधारशिला रखी।
- **नेताजी की प्रतिमा** : इंडिया गेट के पास ब्रिटिश शासक की प्रतिमा हटाकर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है।
- **नया संसद भवन** : 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन। दिसंबर 2020 में पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था।
- **नए संसद भवन की विशेषता** : पुराने संसद भवन से 17 हजार वर्गमीटर बड़ा है, 64,500 वर्गमीटर में फैला है। लोकसभा में 888 जबकि राज्यसभा में 326 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है।
- **संसद का संयुक्त सत्र** : नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के दौरान कुल 1,224 सदस्यों के एक साथ बैठने की व्यवस्था की गई है।
- **राष्ट्रीय पुलिस स्मारक**: 21 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया। **The Wall of Valour** पर उन 34 हजार 844 पुलिस कर्मियों के नाम है, जिन्होंने देश के अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग चुनौतियों से निपटते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

केंद्रीकृत सचिवालय, जिसकी इमारतों का नाम कर्तव्य भवन रखा गया है, इसकी शुरुआत अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने की। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और पूरी परियोजना नए और आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है।

कर्तव्य, देश के कर्मप्रधान दर्शन की मूल भावना है। स्व की सीमा से परे, सर्वस्व को स्वीकार करने की विराट दृष्टि, यही कर्तव्य की वास्तविक परिभाषा है। इसलिए, कर्तव्य, यह केवल इमारत या मार्ग का नाम भर नहीं है। यह करोड़ों देशवासियों के सपनों को साकार करने की तपोभूमि है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, "कर्तव्य ही आरंभ है, कर्तव्य ही प्रारब्ध है। करुणा और कर्मठता के स्नेह सूत्र में बंधा कर्म, वही तो है - कर्तव्य। सपनों का साथ है- कर्तव्य, संकल्पों की आस है- कर्तव्य, परिश्रम की पराकाष्ठा है- कर्तव्य, हर जीवन में ज्योत जला दे, वो इच्छाशक्ति है- कर्तव्य। करोड़ों देशवासियों के अधिकारों की रक्षा का आधार है- कर्तव्य, मां भारती की प्राण-ऊर्जा का ध्वजवाहक है- कर्तव्य, नागरिक देवो भवः के मंत्र का जाप है- कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति भक्ति

- **राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बने स्मारक:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर 23 मार्च 2022 को कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। गैलरी में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के योगदान और ब्रिटिश औपनिवेशिक राज के विरुद्ध उनके सशस्त्र प्रतिरोध को दर्शाया गया है।
- **गैलरी में क्या है खास:** गैलरी में क्रांतिकारी आंदोलन के जन्म, क्रांतिकारियों द्वारा महत्त्वपूर्ण संगठनों का निर्माण, आंदोलन का विस्तार, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन, नौसेना विद्रोह के योगदान आदि को पेश किया गया है।
- **नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2019 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती के अवसर पर लाल किले में नेताजी सुभाष संग्रहालय का उद्घाटन किया और इसे इंडियन नेशनल आर्मी को समर्पित किया।
- **आधुनिक डिफेंस एन्क्लेव के निर्माण की दिशा में बड़ा और महत्वपूर्ण कदम :** सितंबर 2021 में नए रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन। इसमें तीनों सेनाओं और सशस्त्र बलों के लगभग 7,000 अधिकारियों के लिए कार्य करने की जगह उपलब्ध है।

तीन मूर्ति, अब लोकतांत्रिक विरासत

- **तीन मूर्ति भवन :** इस भवन का निर्माण वर्ष 1930 में हुआ था। यह भवन पहले ब्रिटिश सेना के कमांडर-इन चीफ का आवास था, जिसे फ्लैग हाउस कहा जाता था।
- **पहले प्रधानमंत्री का आवास :** भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस भवन को अपना आवास बनाया। उनके निधन के बाद वर्ष 1964 में इसे संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया।

प्रधानमंत्री संग्रहालय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन मूर्ति भवन को भारतीय लोकतंत्र की विरासत के तौर पर सहेजने के लिए 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसकी 43 गैलरी में प्रत्येक प्रधानमंत्री के योगदान का रिकॉर्ड है।

जनमानस पर प्रभाव

यह स्पष्ट प्रतीक है कि भारत अब ब्रिटिश या गुलामी कालखंड की विरासत को नहीं अपनाएगा, यह बदलाव सदैव स्मरण कराएगा कि हमारा इतिहास और पहचान स्वाधीन है, पराधीन नहीं। इससे जनता में अपनापन और राष्ट्रगौरव बढ़ता है।

भाव से किया हर कार्य है- कर्तव्य।" आजादी के अमृत काल में, देश को नई प्रेरणा और नई ऊर्जा मिली है। अब गुजरे हुए कल को छोड़कर, देश आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहा है। हर तरफ जो नई आभा दिख रही है, वह नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। कर्तव्य पथ केवल ईंट-पत्थरों का रास्ता भर नहीं है। यह भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवंत मार्ग बन गया है।

इसी तरह आज अगर राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर कर्तव्य पथ बना है, अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है, तो ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में, "ये न शुरुआत है, न अंत है। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है।"

देश में लंबे समय तक रक्षा क्षेत्र से जुड़ा कामकाज दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए हटमेंट्स से ही चल रहा था। ऐसे

संस्कृति, शिक्षा, इतिहास पर पुनर्विचार

संस्कृति, शिक्षा और इतिहास पर पुनर्विचार का यह दौर मूल्यों, ज्ञान परंपराओं और राष्ट्रीय पहचान को नए दृष्टिकोण से समझने का अवसर प्रदान करता है। यह न केवल वर्तमान पीढ़ी को जड़ों से जोड़ता है, बल्कि भविष्य के लिए एक संतुलित और सशक्त बौद्धिक आधार भी करता है तैयार...

- **औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति से मुक्ति :** 2025 में पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि उस औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति जिसे मैकाले ने 1835 में भारतवर्ष पर थोपा था, उसे 2035 तक पूरी तरह से मुक्त किया जाएगा।
- **भारतीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहन :** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर 2024 को मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने को स्वीकृति दी।

नई शिक्षा नीति-2020

देश में 34 वर्ष बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई जो पूरी तरह से व्यावहारिकता और कौशल पर आधारित है। इसमें मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है।

- **भाषा की नई श्रेणी :** भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2004 को "शास्त्रीय भाषाओं" के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था। इसमें तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया।
- **न्याय शासन :** न्याय शासन में भारतीय भाषाओं को महत्वपूर्ण जगह मिली।
- **भारतीय दृष्टिकोण :** नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा सामग्री में भारतीय दृष्टिकोण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- **भारतीय कानून :** भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023, 1 जुलाई 2024 से लागू। आपराधिक कानून गुलामी की मानसिकता से मुक्त हुआ।

जनमानस पर प्रभाव

आत्म-सम्मान और स्वावलंबन अपने अतीत को गर्व से अपनाने का वातावरण देता है। यह गुलामी की मानसिकता के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण कदम है। पुरानी ब्रिटिश नजरिए से लिखी इतिहास गाथा पर निर्भरता कम हुई। साथ ही अंग्रेजी ही श्रेष्ठ भाषा, उस मानसिकता में कमी आई और स्थानीय भाषाओं का गौरव बढ़ा।

हटमेंट्स जिनको उस समय घोड़ों के अस्तबल और बैरकों से संबंधित जरूरतों के अनुसार बनाया गया था। आजादी के बाद के दशकों में इनको रक्षा मंत्रालय, थलसेना, नौसेना और वायुसेना के दफ्तरों के रूप में विकसित करने के लिए समय-समय पर हल्की-फुल्की मरम्मत हो जाती थी। कोई अधिकारी आने वाले होते थे तो थोड़ा और पेंटिंग कर दी जाती थी। आज 21वीं सदी के भारत की सैन्य ताकत को हर लिहाज से आधुनिक बनाने, एक से एक आधुनिक हथियारों से लैस करने, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के माध्यम से सेनाओं का समन्वय बेहतर बनाने, सेना की जरूरत के अनुसार की खरीद की प्रक्रिया को तेज बनाया जा रहा है। ऐसे में देश की रक्षा-सुरक्षा से जुड़े कामकाज दशकों पुराने हटमेंट्स से हो, यह कैसे संभव हो सकता था। इसलिए इन स्थितियों को बदलना भी बहुत जरूरी था। अब जो डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, यह कार्य-संस्कृति में आए एक और बदलाव एवं सरकार की प्राथमिकता के प्रतिबिंब हैं।

सांस्कृतिक पुनर्जागरण, विरासत और सभ्यता केंद्रों को पुनर्जीवित करना

सांस्कृतिक पुनर्जागरण के इस दौर में मंदिर, तीर्थ, विरासत स्थल और सभ्यता केंद्रों का पुनर्जीवन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति को नई ऊर्जा देता है। ऐसे प्रयास न केवल परंपराओं को पुनर्स्थापित करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध विरासत को जीवंत रूप में भी रखते हैं सुरक्षित...

- **पांचजन्य स्मारक और महाभारत अनुभव केंद्र:** भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में कुरुक्षेत्र में नवनिर्मित 'पांचजन्य' स्मारक का हाल ही में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। वहीं महाभारत अनुभव केंद्र भी पहुंचे।
- **पुनौरा धाम :** बिहार के सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास पर काम शुरू। यह भव्य मंदिर 68 एकड़ से अधिक क्षेत्र में लगभग 890 करोड़ रु. की लागत से बनेगा।
- **स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी:** गुजरात में सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगाई गई जो दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति है। हैदराबाद में दुनिया की सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा 11वीं सदी के वैष्णव संत श्रीरामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी स्थापित की गई है। वहीं, 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलुरु के संस्थापक नाडप्रभु केम्पेगौडा की है।
- **सुहेलदेव स्मारक, संत तुकाराम मंदिर, विट्ठल रुक्मिणी मंदिर:** उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव स्मारक का जून, 2025 में उद्घाटन। वहीं पुणे के देहू में जगद्गुरु श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का भी उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र के देहू में विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में पट्टिका का अनावरण किया गया।

25 नवंबर 2025 को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य-दिव्य-नव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। वहीं, काशी, महाकाल, केदारनाथ, सोमनाथ, अयोध्या मंदिरों का संरक्षण व विरासत से जुड़ी परियोजनाओं पर काम हुआ।

जनमानस पर प्रभाव

नागरिकों में यह भावना मजबूत करना कि हमारी सभ्यता सदियों पुरानी और महान है। यह सीधे गुलामी की मानसिकता को चुनौती देता है, जो भारतीय संस्कृति को हीन बताती थी।

इतना ही नहीं, आजादी के बाद दशकों तक देश की प्रशासनिक तंत्र उन बिल्डिंगों से चलाई जाती रही है, जो ब्रिटिश शासनकाल में बनी थी। दशकों पहले बने इन प्रशासनिक भवनों में वर्किंग कंडीशन खराब हो चुकी थी। कई महत्वपूर्ण मंत्रालय भी करीब 100 साल से एक ही बिल्डिंग में अपर्याप्त संसाधनों के साथ चल रही थी। इतना ही नहीं, भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालय, दिल्ली के 50 अलग-अलग जगहों से चल रहे थे। यह सच्चाई है कि 21वीं सदी के भारत को, 21वीं सदी की आधुनिक व्यवस्थाएं चाहिए, इमारतें भी चाहिए। ऐसी इमारतें जो टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से बेहतरीन हों। जहां कर्मचारी सहज हों, फैसले तेज हों और सेवाएं सुगम हों। इसलिए कर्तव्य पथ के आसपास एक समग्र दृष्टिकोण के साथ कर्तव्य भवन जैसी विशाल इमारतों का निर्माण किया जा रहा है।

अब केंद्र सरकार, एक समग्र दृष्टिकोण के साथ भारत के नव-निर्माण में जुटी है। देश का कोई भी हिस्सा आज विकास की धारा से अछूता नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, अधिकार

नया भारत, बहुत तेजी से बदल रहा है। लाल किले से मैंने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और सबका प्रयास के संबंध में विस्तार से चर्चा की थी। आज ये देखकर बहुत गर्व होता है कि भारत ने, गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर अब स्वतंत्र होने के स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्तव्य के पालन से ही अधिकारों को बल मिलता है। अगर नागरिक से कर्तव्य की अपेक्षा रखते हैं, तो सरकार के लिए भी कर्तव्य सर्वोपरि है। ऐसे में जब कोई सरकार अपने कर्तव्यों को गंभीरता से पूरा करती है, तो वह सुशासन में भी नजर आता है। इसकी बानगी बीते 11 वर्षों में देखने को मिली है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी कई अवसरों पर आह्वान कर चुके हैं, "कर्तव्य की भावना के साथ हम सबको हमेशा राष्ट्र निर्माण में जुटे रहना है। हम सबको यह हमेशा याद रखना है- कर्तव्य की कोख में ही पलते हैं विकसित भारत के सपने।"

बदल रहे गुलामी के हर निशान

हमारी व्यवस्था के हर कोने में गुलामी की इस मानसिकता ने डेरा डाला हुआ था। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति भारतीय संविधान का सम्मान बन रही है। अंग्रेजी कालखंड की लाल बत्ती संस्कृति को पूरी तरह से खत्म किया गया। भारतीय नौसेना का ध्वज, सदियों तक उस ध्वज पर ऐसे प्रतीक बने रहे, जिनका हमारी सभ्यता, हमारी शक्ति, हमारी विरासत से कोई संबंध नहीं था। भारतीय नौसेना के ध्वज से गुलामी के उस प्रतीक को हटाया गया, जिसमें औपनिवेशिक काल की छाप दिखती थी। यह सिर्फ एक डिजाइन में बदलाव नहीं है, यह मानसिकता बदलने का क्षण था। यह वो घोषणा थी कि भारत अब अपनी शक्ति, अपने प्रतीकों से परिभाषित करेगा, न कि किसी और की विरासत से।

दरअसल, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने इसे सत्ता का हस्तांतरण कहा। औपनिवेशिक शासन से हम आजाद

स्वदेशी और आत्मनिर्भरता बनी विकास का केंद्र बिंदु

स्वदेशी और आत्मनिर्भरता आज विकास का नया केंद्र बिंदु बनकर राष्ट्र की आर्थिक और तकनीकी क्षमता को मजबूत दिशा दे रहे हैं। यह परिवर्तन न केवल स्थानीय उत्पादों व नवाचार को प्रोत्साहन देता है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की स्वतंत्र और सशक्त पहचान को भी करता है सुदृढ़...

- **मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल** : भारत सरकार ने 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने और आय एवं रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से 16 सितंबर 2020 को संशोधित सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 जारी किया। यह भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिर्माण एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
- **मेड इन इंडिया चिप** : भारत में, भारत के लोगों द्वारा बनाई गई मेड इन इंडिया चिप जल्द बाजार में आने की संभावना।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता
ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी की ताकत

भारत वर्ष 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन के लक्ष्य पर काम कर रहा है।

रक्षा निर्यात

वर्ष 2029 तक 50,000 करोड़ रुपये रक्षा निर्यात का लक्ष्य।

- **ऑपरेशन सिंदूर** : पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई 2025 को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने तीनों सेनाओं की एक सुनियोजित प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया। ऑपरेशन में सटीकता, व्यावसायिकता और उद्देश्य का समावेश था। पाकिस्तान के भीतर तक फैले आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए दंडात्मक और लक्षित अभियान चलाया गया।
- **स्वदेशी उपकरणों की ताकत** : ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विश्व ने आकाश मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस, आकाश तीर वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली और अन्य स्वदेशी उपकरणों/प्लेटफॉर्म की शक्ति देखी।

खादी बना फैशन और गौरव का प्रतीक

- **खादी से जुड़ रहे फैशन ब्रांड** : आज भारत के टॉप फैशन ब्रांड खादी से जुड़ने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। भारत में खादी का रिकॉर्ड उत्पादन और रिकॉर्ड बिक्री हो रही है।
- **खादी का उत्पादन** : वर्ष 2013-14 में करीब 26 हजार करोड़ रुपये का उत्पादन होता था। यह लगभग चार गुना बढ़कर वर्ष 2024-25 में 1.16 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
- **खादी की बिक्री** : पिछले 10 वर्षों में खादी की बिक्री में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 में 31 हजार करोड़ से ज्यादा, वर्ष 2024-25 में लगभग पांच गुना बढ़ कर 1.70 लाख करोड़ से ज्यादा। 447% की बढ़ोतरी।

जनमानस पर प्रभाव

विदेशी वस्तुएं अच्छी होती हैं, यह धारणा टूटने लगी है। भारत में बनी वस्तुओं पर भरोसा बढ़ने लगा है। अब भारत में बने रक्षा उत्पाद अमेरिका, फ्रांस, अर्मेनिया सहित 100 से ज्यादा देशों को निर्यात हो रहे हैं।

तो हुए पर ऐसे कई प्रतीक, व्यवस्थाएं बनी रहीं। आजादी के बाद करीब 6 दशक तक वे सारी मान्यताएं, धारणाएं और शासकीय व्यवस्थाएं पूर्ववत चलती रहीं जिनकी नींव अंग्रेजों ने डाली थी और औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने के बाद भारत को अपनी मेधा, अपनी प्रतिभा के साथ दुनिया में अपनी भूमिका अदा करने के लिए जिस आत्मविश्वास से खड़ा होना था, वह सही ढंग से नहीं हो पाया। वह भारत जो अपनी सामाजिक पूंजी और सांस्कृतिक परंपरा के बल पर चलता था, वहां यूरोपियन मान्यताएं हावी ही रहीं। यानी देश औपनिवेशिक शासन से तो मुक्त हुआ, लेकिन उसकी मानसिकता से पीछा नहीं छूटा। इन्हीं प्रतीकों को बदलने की पहली शुरुआत हुई आम बजट से। देश में वर्ष 2000 तक आम बजट शाम को पांच बजे पेश किया जाता था। अंग्रेजी शासन काल की यह परंपरा आजादी के पांच दशक से अधिक समय तक बनी रही। अंग्रेजों के समय यह परंपरा इसलिए बनाई गई थी कि लंदन में बैठे अंग्रेजी हुक्मरान सुबह के 11 बजे उस बजट को सुन सकें। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस समय

खेल, विज्ञान से आत्म-विश्वास को मजबूती

खेल, विज्ञान और स्टार्टअप की प्रगति ने युवाओं में आत्मसम्मान और विश्वास पैदा किया है। युवाओं की इन्हीं सफलता से देश को वैश्विक स्तर पर मिल रही है एक नई पहचान...

ओलंपिक प्रदर्शन में बढ़त

- भारत की ओलंपिक यात्रा में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है, जिसने एथलेटिक उत्कृष्टता के एक नए युग को चिह्नित किया।
- 2016 में 117 सदस्यीय दल द्वारा 2 पदकों की मामूली संख्या की तुलना में भारत ने टोक्यो 2020 में 7 पदक जीते और पेरिस 2024 में 6 पदकों के साथ मजबूत प्रदर्शन बनाए रखा।
- नीरज चोपड़ा, एथलेटिक्स (भाला) में भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता (टोक्यो 2020) बने।

चंद्रयान 3 की सफलता, गगनयान जैसे अभियान

- भारत सरकार ने चंद्रयान-3 मिशन की सफलता का जश्न मनाने के लिए 23 अगस्त को 'राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस' घोषित किया।
- इसके साथ, भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है।
- भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन 'गगनयान' सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2027 की पहली तिमाही का लक्ष्य है।
- भारत की अंतरिक्ष भविष्यदृष्टि योजना 2047 के हिस्से के तहत 2040 तक पहले मानवयुक्त चंद्र मिशन की योजना है।
- **स्टार्टअप संस्कृति का विस्तार**: उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत दो लाख से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी।
- **दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम** : भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
- **रोजगार** : इन स्टार्टअप के माध्यम से 17.6 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित हुए हैं और विविध क्षेत्रों में नए अवसर पैदा हुए।
- यूनिकॉर्न : भारत में वर्ष 2025 तक यूनिकॉर्न की संख्या 118 से अधिक जबकि वर्ष 2014 में केवल चार यूनिकॉर्न थे। यह मजबूत घरेलू नवाचार और निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।

जनमानस पर प्रभाव

युवाओं में यह भावना बढ़ी है कि हम भी कर सकते हैं। यह गुलामी की मानसिकता के विपरीत है।

को बदला और 2001 से दिन में 11 बजे बजट पेश होना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो कदम आगे बढ़ाते हुए बजट की तारीख को 28 फरवरी की जगह 1 फरवरी किया और 92 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया। इन कदमों से देश की बजट प्रक्रिया गुलामी के अंश से पूरी तरह मुक्त हो गई। 2016 तक प्रधानमंत्री आवास के नजदीक वाले रोड को रेस कोर्स रोड कहा जाता था। लेकिन उसका नाम लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। रेस कोर्स नाम अंग्रेजों का दिया हुआ था, जिसे हटाने के लिए आजादी के बाद इतने लंबे अरसे तक किसी ने ध्यान नहीं दिया या यूं कहें कि औपनिवेशिक मानसिकता को ही जीवन का हिस्सा बना लिया था। इतना ही नहीं, गणतंत्र दिवस समारोह के बाद होने वाले बीटिंग रिट्रीट सेरिमनी से प्रेयर गीत- 'अबाइड विद मी' को हटा दिया गया। उसकी जगह पर कवि प्रदीप के मशहूर गीत- 'ऐ मेरे वतन के लोगों' को शामिल किया गया। अमर जवान ज्योति की लौ का राष्ट्रीय समर स्मारक में विलय कर दिया गया। नेताजी सुभाषचंद्र बोस की

डिजिटल आत्मनिर्भरता

पिछले एक दशक से भारत सरकार की नीतियों ने देश के लोगों को डिजिटली आत्मनिर्भर बनाया है। पैसे की लेनदेन से लेकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने वैश्विक मंच पर भी दिखाई है अपनी ताकत...

यूपीआई और डिजिटल लेनदेन

- भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (**UPI**) अब दुनिया का नंबर वन रीयल-टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। इसने दैनिक लेनदेन की प्रोसेसिंग में वीजा को पीछे छोड़ते हुए बढ़त हासिल कर ली है।
- यूपीआई भारत के 85% और वैश्विक स्तर पर 50% डिजिटल भुगतानों को संचालित करता है।

डिजिटल इंडिया

- डिजिलॉकर के 53.92 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ता, उमंग 23 भाषाओं में 2,300 सेवाएं प्रदान करता है।
- भारतनेट ने 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा।

5G, 6G भारतीय तकनीक

- अक्टूबर 2022 में 5**G** लॉन्च हुआ, जिसने डिजिटल सेवाओं को और भी तेज कर दिया।
- 22 महीनों में, भारत ने 4.74 लाख 5**G** टावर लगाए जो 99.6% जिलों को कवर करते हैं। अकेले 2023-24 में 2.95 लाख टावर जोड़े गए।
- 86 प्रतिशत से अधिक घर अब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं।
- 22 मार्च, 2023 को 'भारत 6**G** विजन' दस्तावेज जारी किया गया, जिसमें भारत को साल 2030 तक 6**G** प्रौद्योगिकी के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में अग्रणी योगदानकर्ता के रूप में देखा गया।

जनमानस पर प्रभाव

अब यह समृद्ध लोगों तक सीमित नहीं, गांव के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति भी सहजता से तकनीकी गौरव का लाभ ले रहा है। यह दर्शाता है कि भारत तकनीक में मार्गदर्शक बन सकता है।

अंडमान निकोबार द्वीप की ऐतिहासिक यात्रा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंडमान स्थित हैवलॉक द्वीप को स्वराज, नील द्वीप को शहीद द्वीप और रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम दिया। लाल किले में नेताजी को समर्पित क्रांति मंदिर नाम से संग्रहालय, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में ब्रिप्लॉवी भारत गैलरी बनाई। नेताजी के शौर्य और पराक्रम भरी जीवन गाथा से जन-जन को जोड़ने के लिए उनके जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में नेताजी की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा की स्थापना की गई। वर्ष 2022 में 8 सितंबर को उसी स्थान पर ग्रेनाइट से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण हुआ। आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। अब गुलामी के प्रतीक को मिटाकर स्थापित की गई नेताजी की प्रतिमा देश के लिए जीने-मरने की हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। यह बदलाव केवल प्रतीकों तक ही सीमित नहीं है,

स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को जनभागीदारी का उत्सव बनाना

स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रम और यहां से होने वाले उद्घोष ने देश के लोगों में सहभागिता का भाव जगाया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से देश के नागरिकों ने मनाया है जनभागीदारी का उत्सव...

- **स्वतंत्रता दिवस समारोह में बदलाव** स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को लाल किले पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। पहली बार वर्ष 2022 में इसके लिए डीआरडीओ निर्मित स्वदेशी तोपों के इस्तेमाल की शुरुआत हुई।
- **गणतंत्र दिवस समारोह में बदलाव** गणतंत्र दिवस समारोह के बाद होने वाले बीटिंग रीट्रीट सेरेमनी से प्रेयर गीत- 'अबाइड विद मी' को हटा दिया गया। उसकी जगह पर कवि प्रदीप के मशहूर गीत- 'ऐ मेरे वतन के लोगों' को शामिल किया गया।
- **मिशन अमृत सरोवर**: केंद्र सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक प्रमुख पहल के रूप में 2022 में मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य देश भर के प्रत्येक जिले में 75 जल स्रोतों का निर्माण और पुनरुद्धार करना है, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिले।
- **आजादी का अमृत महोत्सव** भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उठे देशभक्ति के उत्साह को फिर से जगाना और नया स्वरूप देना, स्वतंत्रता सेनानियों विशेष रूप से गुमनाम नायकों के योगदान को याद करना था।

हर घर तिरंगा

आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में 2022 में शुरू किया गया यह अभियान अब एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया है। इसमें भारत के कोने-कोने और दुनिया भर के भारतीयों ने भाग लिया है। 16 अगस्त 2025 को शाम 6 बजे तक भारत ने 7.50 करोड़ सेल्फी अपलोड करके हर घर तिरंगा अभियान मनाया।

जनमानस पर प्रभाव

सरकार और जनता के बीच मनोवैज्ञानिक दूरी कम हो रही है। भारतीयता का भाव भरने, सरकार के साथ भागीदार बनने में मददगार साबित हो रही है।

यह बदलाव देश की नीतियों का भी हिस्सा बन चुका है। आज देश अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को बदल चुका है।

गुलामी की मानसिकता से मुक्त होते आत्मनिर्भर भारत की पहल में भारतीय न्याय संहिता इतिहास में एक गौरवपूर्ण क्षण है। अब भारत का अपना ऐसा कानून है जो पूरी तरह स्वदेशी के भाव से भरा है, जिसका ध्येय दंड नहीं, न्याय है। भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023, 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। इससे आपराधिक कानून गुलामी की मानसिकता से मुक्त हुए हैं। भारत में अब स्वदेशी न्याय प्रणाली अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों की जगह ले चुकी है। आम आदमी के हितों पर केंद्रित कानून नागरिकों के अधिकारों को सर्वोच्च रखकर समाज के हर तबके की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाला है। आधुनिक एवं आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी न्याय प्रणाली आम लोगों को पारदर्शी और जल्द न्याय प्रदान करने का काम कर रही है।

मेरी माटी-मेरा देश

31 अक्टूबर 2023 को आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 36 राज्यों एवं केंद्र-शासित प्रदेशों के 20 हजार से अधिक प्रतिनिधि 8,000 से अधिक अमृत कलशों के साथ राष्ट्रीय राजधानी पहुंचें।

जी-20 में जन भागीदारी

जी-20 जनभागीदारी आंदोलन में देश भर के विभिन्न स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों और कौशल विकास संस्थानों से रिकॉर्ड युवाओं ने भाग लिया। जी-20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट पहल के तहत देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सांस्कृतिक गौरव की नई गाथा

गुलामी के कालखंड में जिन अत्याचारियों ने भारत को कमजोर करने के प्रयास किए। इसके लिए सबसे पहले हमारे प्रतीकों को ही निशाना बनाया था। आजादी के 7 दशक बाद आज समय का चक्र एक बार फिर घूमा है। देश अब लाल किले से 'गुलामी की मानसिकता से मुक्ति' और अपनी 'विरासत पर गर्व' की घोषणा कर रहा है। यही परिवर्तन आज सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बने अयोध्या में भी दिख रहा है। यह गुलामी की मानसिकता ही है,

हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में अब भारतीय वाद्य यंत्रों की भी गूंज सुनाई देती है। बीटिंग रिट्रीट समारोह में अब देशभक्ति से सराबोर गीतों को सुनकर हर भारतीय आनंद से भर जाता है।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

कोई भी देश बिना आत्मविश्वास के आगे नहीं बढ़ सकता। दुर्भाग्य से लंबी गुलामी ने भारत के इसी आत्मविश्वास को हिला दिया था। इसकी वजह थी, गुलामी की मानसिकता। गुलामी की ये मानसिकता, विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसलिए, आज का भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने के लिए काम कर रहा है।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा। भगवान राम, अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम हैं। ओरछा के राजा राम से लेकर, रामेश्वरम के भक्त राम तक, शबरी के प्रभु राम से लेकर, मिथिला के पाहुन राम जी तक, भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण-कण में राम हैं। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। समय का पहिया घूमा है और जो काम सोमनाथ से शुरू हुआ था, वह अब एक अभियान बन गया है। आज काशी में विश्वनाथ धाम की भव्यता भारत के अविनाशी वैभव की गाथा गा रही है। आज महाकाल महालोक हमारी अमरता का प्रमाण दे रहा है। आज केदारनाथ धाम भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बुद्ध सर्किट का विकास करके भारत एक बार फिर दुनिया को बुद्ध की तपोभूमि पर आमंत्रित कर रहा है। देश में राम सर्किट के विकास के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। 2025 के समापन से पूर्व धर्म-ध्वजा के आरोहण के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूर्ण हो गया है। इस पुनर्जागरण के साथ ही अब समय आ गया है कि अगर हम ठान लें, अगले दस साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे और उससे ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। आने वाले एक हजार वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी, जब मैकाले की गुलामी की परियोजना को अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखा देंगे। कोई भी राष्ट्र समग्र विकास की ओर कदम तभी बढ़ा पाता है, जब देश अपनी सामाजिक सच्चाईयों और सांस्कृतिक पहचान का समावेश करता है।

नया एजेंडा

आजादी के 100वें वर्ष तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनकर रहेगा। इस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए देश हर क्षेत्र में तेज गति से कर रहा है विकास...

- भारत को 2047 तक सभी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर भारत को विकसित बनाने का संकल्प आजादी के अमृत महोत्सव में लिया गया। इसके लिए स्वदेशी की भावना के अनुरूप योजनाएं, नीतियों और पहल की शुरुआत की गई। इस विजन में केवल भौतिक विकास नहीं, मानसिक आजादी, सामाजिक-आर्थिक आत्मनिर्भरता, अधिकार और कर्तव्य की समझ शामिल है।
- **विकसित भारत के केंद्र में युवा:** भारत की लगभग 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। यह जीवंत और गतिशील पीढ़ी 2047 तक विकसित भारत बनने की राष्ट्र की कल्पना का केंद्र बिंदु है।

- **युवाओं के लिए पहलः** बीते 11 वर्षों में युवाओं के लिए की गई पहलों से होने वाला परिवर्तन जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। कुशल पेशेवर, स्थायी व्यवसाय, एथलीटों की वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है तो अधिक युवा नेता समुदायों को आकार दे रहे हैं।
- **माई भारतः** माई भारत कौशल विकास, सामुदायिक सेवा, फिट इंडिया, स्वच्छता, आपदा तैयारी और सामाजिक जागरूकता पर कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को जोड़ता है।
- **पीएम विकसित भारत रोजगार योजनाः** देश के युवा राष्ट्र के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाएं, इसी उद्देश्य से पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई। 1 लाख करोड़ रुपये की इस योजना के तहत 3 करोड़ युवा भारतीयों को लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- **परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुनाः** 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को दस गुना बढ़ाने का संकल्प है। इस योजना के तहत 10 नए परमाणु रिएक्टर निर्माणाधीन हैं, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास सुनिश्चित होगा।
- **एक ही लक्ष्यः** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि हर संस्था, हर व्यक्ति को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हर प्रयास और कार्य विकसित भारत के लिए होगा।

बीते कुछ वर्षों में हुई पहल का ही परिणाम है कि राष्ट्रीय प्रतीकों में औपनिवेशिक और गुलामी के प्रतीकों की छाया कम हुई है। ज्ञान और संस्कृति में भारतीय दृष्टिकोण मजबूत हुआ है। शिक्षक और नौकरशाही को कर्मयोगी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है।

जनमानस पर प्रभाव

यह दर्शाता है कि गुलामी की मानसिकता केवल प्रतीकात्मक बदलाव से नहीं जाएगी। इसके लिए स्थायी, व्यापक, विकास आधारित आत्मनिर्भरता की सोच और नई राष्ट्रीय संस्कृति की जरूरत है।

सकारात्मक विरासत का संरक्षण

जब सफल राष्ट्र आगे बढ़ते हैं, तो अपनी सकारात्मक विरासत को त्यागते नहीं हैं, वो उसे संरक्षित करते हैं। आज 'विकास और विरासत' के इसी विजन पर भारत आगे बढ़ रहा है। नए कर्तव्य भवन के बाद नॉर्थ और साउथ ब्लॉक भी भारत की महान विरासत का हिस्सा बनेंगे। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को देश की जनता के लिए 'युगे युगीन भारत', संग्रहालय के रूप में बदला जा रहा है। देश का हर नागरिक यहां जा सकेगा, देश की ऐतिहासिक यात्रा के दर्शन कर सकेगा।

निश्चित रूप से बीते कुछ वर्षों से देश का विचार और देश का व्यवहार दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं। यही संकल्प राष्ट्र को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। अब इस नववर्ष यानी 2026 से 2035 की 10 वर्षीय यात्रा में भारत ने ठान लिया है कि मैकाले द्वारा वर्ष 1835 में किए गए उस अपराध को वर्ष 2035 में जब 10 साल के बाद 200 साल होंगे, उस सोच से मुक्ति पाकर रहेंगे। ■

आत्मविश्वासी भारत

अनिश्चितताओं से भरी 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। इन 25 वर्षों में वित्तीय संकट, वैश्विक महामारी, युद्ध की स्थितियों ने दुनिया को किसी न किसी रूप में चुनौती दी। इन सबके बीच भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2025 में कहा कि आत्मविश्वासी भारत आज के रिफॉर्म और परफॉर्म से बना रहा है कल के ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता...

भारत के दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े देश की प्रगति की नई गति को बता रहे हैं। दूसरी तीमाही में जीडीपी विकास दर 8.2 फीसदी रही। यह एक सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि यह मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत है। यह इस बात का भी संकेत है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये आंकड़े तब हैं, जब वैश्विक विकास की दर 3 प्रतिशत के आसपास है। जी-7 देशों की अर्थव्यवस्था की औसत विकास दर डेढ़ प्रतिशत के करीब है। इन परिस्थितियों में भी भारत उच्च विकास और निम्न महंगाई दर का मॉडल बना हुआ है। एक समय था, जब देश में खासकर अर्थशास्त्री उच्च महंगाई दर को लेकर चिंता जताते थे। आज वही महंगाई कम होने की बात करते हैं। जब दुनिया में आर्थिक सुस्ती की बात होती है, तब भारत विकास की कहानी लिखता है। जब दुनिया में विश्वास का संकट दिखता है, तब भारत विश्वास का स्तंभ बन रहा है।

भारत के सामर्थ्य का एक बड़ा हिस्सा एक लंबे समय तक अनछुआ रहा है। जब देश के इस अनछुई क्षमता को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे, जब वो बिना किसी रुकावट के देश के विकास में भागीदार बनेंगे, तो देश का कायाकल्प होना तय है। पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट, गांव, टियर टू और टियर थ्री शहर, नारी शक्ति, युवा शक्ति, सामुद्रिक शक्ति, अंतरिक्ष क्षेत्र की क्षमता के साथ देश अब आगे बढ़ रहा है। भारत की नारी शक्ति तो कमाल कर रही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अब सिर्फ महिला सशक्तीकरण तक सीमित नहीं है, ये समाज की सोच और सामर्थ्य, दोनों को ट्रांसफार्म कर रहा है। रुकावटें हटाई गईं तो इन क्षमताओं को नए पंख लगे। अंतरिक्ष क्षेत्र पहले सरकारी नियंत्रण में था, अब रिफॉर्म कर इसे निजी क्षेत्र के लिए खोला गया।

देश में आज राष्ट्रीय लक्ष्यों को देखते हुए सुधार किए जा रहे हैं। हर क्षेत्र में कुछ न कुछ बेहतर हो रहा है, देश की गति स्थिर है, दिशा लगातार सही है और सरकार का इरादा 'राष्ट्र प्रथम' का है। 2025 में बहुत से रिफॉर्म्स हुए। सबसे बड़ा रिफॉर्म नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी का था। इन सुधारों का असर देखने को मिला और आमजन को इसका व्यापक लाभ

भारत में हो रहा परिवर्तन केवल संभावनाओं की बात नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए जीवन, बदलती हुई सोच और बदलती हुई दिशा की सच्ची गाथा है।

आज के भारत की ये यात्रा, सिर्फ विकास की नहीं है। ये सोच में बदलाव की भी यात्रा है, ये मनोवैज्ञानिक पुनर्जागरण, साइकोलॉजिकल रेनसां की भी यात्रा है।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

भी मिला है। 12 लाख रुपये तक की आय पर जीरो टैक्स, यह एक ऐसा कदम रहा, जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था। पहले बैंक से हजार रुपये का भी लोन लेना होता था, तो बैंक गारंटी मांगता था, क्योंकि अविश्वास बहुत अधिक था। बीते दशक में सरकार ने अविश्वास के कुचक्र को तोड़ा है। मुद्रा योजना में अभी तक 37 लाख करोड़ रुपये गारंटी फ्री लोन दिए जा चुके हैं जिससे नौजवानों को भी आंत्रप्रन्योर बनने का विश्वास मिला है। रेहड़ी-पटरी वालों को भी बिना गारंटी बैंक से पैसा मिल रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 11 वर्षों में किए गए कार्यों और पुराने समय में की गई चूक की बात की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान 4-5 दशक पहले शुरू हो गए होते, सेमीकंडक्टर लगाने के लिए देश में आई कंपनी को तवज्जो दी गई होती, ऊर्जा क्षेत्र पर ध्यान दिया गया होता तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। भारत हर साल करीब-करीब 125 लाख करोड़ रुपये के पेट्रोल-डीजल-गैस का आयात करता है। देश में 2014 तक सौर ऊर्जा क्षमता सिर्फ 3 गीगावॉट थी, पिछले 10 वर्षों में अब ये बढ़कर 130 गीगावॉट के आसपास पहुंच चुकी है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 2014 से पहले तक देश अपनी जरूरत का 75 फीसदी आयात करता था जो अब करीब-करीब जीरो हो गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में कहा कि 2014 के बाद हमने एक रिफॉर्म किया, देश ने परफॉर्म किया। उसके परिवर्तनकारी नतीजे आज दुनिया देख रही है। भारत की ये उपलब्धियां सामान्य बात नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये एक फंडामेंटल चेंज है, जो बीते दशक में भारत लेकर आया है। ये फंडामेंटल चेंज रजीलियन्स का है, ये चेंज समस्याओं के समाधान की प्रवृत्ति का है, ये चेंज आशंकाओं के बादलों को हटाकर, आकांक्षाओं के विस्तार का है। इसी वजह से आज का भारत खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है और आने वाले कल को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। हमें ये भी समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो विश्वास पैदा हुआ है, उसका आधार वर्तमान में हो रहे कार्यों की एक मजबूत नींव है। ■

‘वंदे मातरम’

भारतवर्ष की रग-रग में रचा-बसा

वंदे मातरम...जिसने भारत को स्वावलंबन का रास्ता दिखाया, वंदे मातरम...जिसने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी, वंदे मातरम...जो विदेशी कंपनियों को चुनौती देने का मंत्र बना, वंदे मातरम...जिसने उस विचार को पुनर्जीवित किया जो हजारों वर्षों से भारत की रग-रग में बसा था। वंदे मातरम के 150 वर्ष ऐसे समय में पूरे हो रहे हैं जब इतिहास की कई प्रेरक अध्याय फिर से हमारे सामने हैं। इसी दौरान लोकतंत्र के मंदिर ‘संसद’ में वंदे मातरम पर 8 दिसंबर को विशेष चर्चा की शुरुआत हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनेक पड़ावों से गुजरी है वंदे मातरम की 150 वर्ष की यह यात्रा। पेश है संपादित अंश...

महर्षि अरविंद ने कहा था कि वंदे मातरम भारत के पुनर्जन्म का मंत्र है जो वंदे मातरम की महत्ता को बताता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर महिमामंडन और गौरव गान से बच्चे, किशोर, युवा और आने वाली कई पीढ़ियां इसके महत्व को समझेंगी। वंदे मातरम की रचना में बहुत बारीकी से भारतवर्ष की मूल सभ्यता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और देश की मां के रूप में कल्पना कर उसकी आराधना करने की परंपरा को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने पुनर्स्थापित किया। इस राष्ट्र गीत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रसार हुआ और इसने बिना किसी प्रचार के हर व्यक्ति के मन को छुआ। वंदे मातरम एक प्रकार से भारत की संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी लोगों के पुनर्जागरण का मंत्र बन गया है।

वंदे मातरम का पुनः स्मरण बहुत बड़ा सौभाग्य

जिस जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुनः स्मरण करना, हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य है। यह एक ऐसा कालखंड, जो हमारे सामने इतिहास के अनगिनत घटनाओं को सामने लेकर आता है।

वंदे मातरम की 100वीं वर्षगांठ पर संविधान की हत्या

वंदे मातरम को जब 50 वर्ष हुए, तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था। वंदे मातरम के 100 साल हुए, तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। देशभक्ति के लिए जीने-मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था।

आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे, उसे पूरा करने का अवसर

वंदे मातरम के 150 वर्ष गौरव पर्व के रूप में स्थापित करने का अवसर है। यही वंदे मातरम है, जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। वंदे मातरम की जिस भावना ने देश की आजादी का जंग लड़ा, फिर से एक बार अवसर है आओ, हम

वंदे मातरम, राष्ट्र की शक्ति है, राष्ट्र को भावनाओं से जोड़ने वाला सामर्थ्यवान एक ऊर्जा प्रवाह है। यह संस्कृति की अविरल धारा का प्रतिबिंब और प्रकटीकरण है। यह सिर्फ स्मरण करने का काल नहीं, नई ऊर्जा-नई प्रेरणा लेने का काल बन जाए। हम उसके प्रति समर्पित होते चलें।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सब देश को साथ लेकर चलें, आजादी का दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए वंदे मातरम के 150 वर्ष हम सब की प्रेरणा-ऊर्जा बने। देश आत्मनिर्भर बने, 2047 में विकसित भारत बने।

अंग्रेजी साजिश के खिलाफ वंदे मातरम बना ढाल

वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र ने 1875 में की थी। गीत ऐसे समय में लिखा गया था, जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी। भारत पर भांति-भांति के दबाव डाल रहे थे, जुल्म कर रहे थे। अंग्रेज अपने राष्ट्रीय गीत- God Save The Queen को भारत में घर-घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चला रहे थे। ऐसे समय में बंकिम दा ने चुनौती दी। उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। इसके कुछ वर्ष बाद, 1882 में जब उन्होंने आनंद मठ लिखा, तो उस गीत का उसमें समावेश किया गया।

वंदे मातरम ने जगाई सदियों पुरानी चेतना

वंदे मातरम ने हमारी सदियों पुरानी उस चेतना को जगाया जो हजारों वर्ष से भारत की रग-रग में रचा-बसा था। वंदे मातरम, सिर्फ राजनीतिक आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था, वो उससे कहीं आगे था। जब वंदे मातरम कहते हैं, तो वेद काल की बात हमें याद आती है। वेद काल से कहा गया है 'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः' अर्थात यह भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। यही वह विचार है, जिसको प्रभु श्रीराम ने भी लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी'।

हमें आत्मनिर्भर बनना है, 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के स्वप्न को साकार करना है। अगर आजादी से 50 साल पहले कोई आजाद भारत का सपना देख सकता था, तो 2047 से 25 साल पहले हम भी एक समृद्ध और विकसित भारत का सपना देख सकते हैं। उसे साकार करने के लिए खुद को समर्पित कर सकते हैं।

वंदे मातरम की स्तुति...

बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब वंदे मातरम की रचना की, तो स्वाभाविक ही वह स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। इसलिए वंदे मातरम की स्तुति में लिखा गया था, "मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय, स्वार्थ का बलिदान है, ये शब्द है वंदे मातरम, है संजीवनी मंत्र भी, यह विश्व विजयी मंत्र भी, शक्ति का आह्वान है, यह शब्द वंदे मातरम। उष्ण शोणित से लिखो, वक्तस्थलि को चीरकर वीर का अभिमान है, यह शब्द वंदे मातरम।"

भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी...

अंग्रेजों के उस दौर में भारत को कमजोर, निकम्मा, आलसी, कर्महीन और नीचा दिखाने का एक फैशन बन गया था। तब बंकिम बाबू ने उस हीन भावना को भी झकझोरते और भारत के सामर्थ्यशाली रूप को प्रकट करते हुए लिखा था- त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी, कमला कमलदलविहारिणी, वाणी विद्यादायिनी। नमामि त्वां नमामि

राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विशेष चर्चा की शुरुआत की

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर 9 दिसंबर को राज्यसभा में विशेष चर्चा की शुरुआत की। चर्चा में उन्होंने कहा कि गुलामी के कालखंड में हमारे कई मंदिर, विश्वविद्यालय, कला केंद्र, कृषि और शिक्षा व्यवस्था को तोड़ दिया गया लेकिन हमारी संस्कृति के भाव को कोई नहीं मिटा सका। उस वक्त भाव को जागृत एवं पुनर्संगठित करने के लिए बंकिम बाबू ने वंदे मातरम की रचना की। इसे न अंग्रेज रोक सके और न उस सभ्यता को स्वीकार करने वाले लोग रोक सके।

वंदे मातरम कभी अप्रासंगिक नहीं होगा। जब वंदे मातरम की रचना हुई, तब इसकी जरूरत जितनी थी, आज भी उतनी है। उस समय वंदे मातरम देश को आजादी दिलाने का माध्यम बना, जबकि अमृत काल में वंदे मातरम देश को विकसित और महान बनाने का नारा बनेगा।

-अमित शाह, ***केंद्रीय गृह मंत्री***

अमित शाह का राज्यसभा में विशेष चर्चा को देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

प्रधानमंत्री की लोकसभा में विशेष चर्चा को देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

कमलाम्, अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥ अर्थात भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी हैं और दुश्मनों के सामने अस्त्र-शस्त्र धारण करने वाली चंडी भी हैं।

शायद दुनिया में कभी उपलब्ध नहीं होगा ऐसा भाव काव्य

क्या कभी किसी ने सोचा है कि आजादी जंग के हर पड़ाव, वो पूरी यात्रा वंदे मातरम की भावनाओं से गुजरता था। उसके तट पर पल्लवित होता था, ऐसा भाव काव्य शायद दुनिया में कभी उपलब्ध नहीं होगा। पूरे विश्व को पता होना चाहिए कि गुलामी के कालखंड में भी ऐसे लोग हमारे यहां पैदा होते थे, जो इस प्रकार के भाव गीत की रचना कर सकते थे। यह विश्व के लिए अजूबा है। हमें गर्व से कहना चाहिए, तो दुनिया भी मनाना शुरू करेगी। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था-एक कार्ये सोंपियाछि सहस्र जीवन-वंदे मातरम अर्थात एक सूत्र में बंधे हुए सहस्त्र मन, एक ही कार्य में अर्पित सहस्त्र जीवन, वंदे मातरम।

वंदे मातरम ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी, कानूनी प्रतिबंध लगा

बंकिम बाबू के गीत ने अंग्रेजों को हिला दिया। गीत की ताकत ही थी कि अंग्रेजों को उस पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बारीसाल में वंदे मातरम गाने पर सर्वाधिक जुल्म हुए थे। वो बारीसाल आज भारत का हिस्सा नहीं रहा है। तब बारीसाल की वीरांगना सरोजिनी घोष, जिन्होंने कहा था-जब तक प्रतिबंध नहीं हटता है, मैं अपनी चूड़ियां निकाल दूंगी।

चट्टान बना वंदे मातरम

अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल के टुकड़े करने की दिशा में काम किया। अंग्रेजों ने 1905 में यह पाप किया, तो वंदे मातरम चट्टान की तरह

महापुरुषों का सपना था स्वतंत्र भारत का, आज की पीढ़ी का सपना है समृद्ध भारत का, वंदे मातरम की भावना ने स्वतंत्रता के स्वप्न को पोषित किया, उसी तरह यह समृद्ध भारत के स्वप्न को भी पोषित करेगी। वंदे मातरम का हम ऋण स्वीकार करें, वंदे मातरम की भावनाओं को लेकर चलें, देशवासियों को साथ लेकर चलें। इस सपने को पूरा करें।

नवंबर, 2026 तक चार चरण में वंदे मातरम का यशोगान

वंदे मातरम की 150 वीं वर्षगांठ को लेकर 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर तय किया कि अगला पूरा साल वंदे मातरम का यशोगान किया जाएगा। वंदे मातरम के यशोगान का पहला चरण नवंबर, 2025 में हुआ। दूसरा चरण जनवरी 2026, तीसरा चरण अगस्त 2026 और चौथा चरण नवंबर 2026 में होगा।

खड़ा रहा। उस समय एक गीत गूंजता था बंगाल में- जाए जाबे जीवोनो चोले, जाए जाबे जीवोनो चोले, जोगोतो माझे तोमार कांधे वंदे मातरम बोले अर्थात हे मां संसार में तुम्हारा काम करते और वंदे मातरम कहते जीवन भी चला जाए, तो वह जीवन भी धन्य है।

वंदे मातरम गाते-गाते फांसी के तख्त पर चढ़े जांबाज सपूत

हमारे जांबाज सपूत बिना किसी डर के फांसी के तख्त पर चढ़ते थे। आखिरी सांस तक 'वंदे मातरम' उनका भाव घोष रहता था। खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, रामकृष्ण विश्वास अनगिनत ऐसे हैं जिन्होंने वंदे मातरम कहते-कहते फांसी के फंदे को अपने गले पर लगाया था। एक भारत, श्रेष्ठ भारत, इन सबका मंत्र एक ही था, वंदे मातरम।

वंदे मातरम ने दिखाया स्वावलंबन का रास्ता

वंदे मातरम ने भारत को स्वावलंबन का रास्ता भी दिखाया। उस समय माचिस की डिबिया से लेकर बड़े-बड़े शिप पर भी वंदे मातरम लिखने की परंपरा बन गई थी। बाहरी कंपनियों को चुनौती देने का एक माध्यम और स्वदेशी का एक मंत्र बन गया। 1907 में जब वी ओ चिदंबरम पिल्लई ने स्वदेशी कंपनी का जहाज बनाया, तो उस पर भी लिखा था वंदे मातरम। राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती ने वंदे मातरम को तमिल में अनुवाद किया, स्तुति गीत लिखे। भारत का ध्वज गीत वी सुब्रमण्यम भारती ने ही लिखा था। उस ध्वज गीत के वर्णन में वंदे मातरम लिखा हुआ था।

हम हर बच्चे के मन में वंदे मातरम के संस्कार को पुनः जागृत करें, हर किशोर के मन में वंदे मातरम का नारा प्रस्थापित करें। हर युवा को वंदे मातरम की व्याख्या के रास्ते पर अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित करें। स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस भारत की कल्पना की थी, वंदे मातरम का उद्घोष उस भारत की रचना का कारण बने।।

वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ?

जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में, जो भी देश के लिए जीता-जागता, उन सबके लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी। तो फिर पिछली सदी में वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वह कौन सी ताकत थी, जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई? मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। 26 अक्टूबर, 1937 को कांग्रेस कार्यसमिति ने एक समीक्षा बैठक कर वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए।

संकट में वंदे मारतम की भावना के साथ आगे बढ़ा देश

किसी भी राष्ट्र का चरित्र, उसकी जीवटता उसके अच्छे कालखंड से ज्यादा, जब चुनौतियों का कालखंड होता है, तब प्रकट होती हैं। 1947 में देश आजाद हुआ तो चुनौतियां और प्राथमिकताएं बदली, लेकिन देश का चरित्र वही रहा। भारत पर जब-जब संकट आए, देश हर बार वंदे मातरम की भावना के साथ आगे बढ़ा। हर संकट में देश वंदे मातरम के भाव के साथ खड़ा हुआ, चुनौतियों को परास्त कर आगे बढ़ा है।

भारत और नेचुरल फार्मिंग... भविष्य की राह!

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लिंक्डइन पोस्ट पर लिखे एक आलेख में प्राकृतिक खेती पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कोयंबटूर में प्राकृतिक खेती पर आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया। इस आयोजन ने प्रधानमंत्री मोदी के मन पर गहरी छाप छोड़ी। अपने लिंक्डइन पोस्ट में इसी पर कुछ विचार बताए, साथ ही पूरे भारत के लोगों से प्राकृतिक खेती को बढ़ाने की अपील की। आलेख पर एक नजर...

वर्ष 2025 के अगस्त में, तमिलनाडु के कुछ किसानों का एक समूह मुझसे मिलने आया और उन्होंने बताया कि कैसे वे स्थिरता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई कृषि तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कोयंबटूर में नेचुरल फार्मिंग पर आयोजित होने वाले एक शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और वादा किया कि मैं कार्यक्रम के दौरान उनके बीच रहूंगा। इसलिए, कुछ सप्ताह पहले, 19 नवंबर को, मैं दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेने के लिए खूबसूरत शहर कोयंबटूर में था। एमएसएमई की रीढ़ माने जाने वाले इस शहर में प्राकृतिक खेती पर एक बड़ा आयोजन हो रहा था।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, नेचुरल फार्मिंग भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और आधुनिक पर्यावरणीय सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें फसलों की खेती बिना रासायनिक पदार्थों के की जाती है। यह विविध क्षेत्रों को बढ़ावा देती है, जहां पौधे, पेड़ और पशुधन एक साथ प्राकृतिक जैव-विविधता को मजबूत करते हैं। यह पद्धति बाहरी इनपुट की जगह खेत में उपलब्ध अवशेषों के पुनर्चक्रण, मल्चिंग और मिट्टी को हवा देने के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने पर जोर देती है।

कोयंबटूर में यह शिखर सम्मेलन हमेशा मेरी स्मृति का हिस्सा रहेगा! यह मानसिकता, कल्पना और आत्मविश्वास में बदलाव का संकेत था जिसके साथ भारत के किसान और कृषि-उद्यमी कृषि के भविष्य को आकार दे रहे हैं।

कार्यक्रम में तमिलनाडु के किसानों के साथ संवाद शामिल था, जिसमें उन्होंने नेचुरल फार्मिंग में अपने प्रयास प्रस्तुत किए और मैं आश्चर्यचकित रह गया!

मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग, जिनमें वैज्ञानिक, एफपीओ लीडर, प्रथम-पीढ़ी के स्नातक, परंपरागत किसान और खासतौर पर उच्च वेतन वाली कॉर्पोरेट करियर छोड़ने वाले लोग शामिल थे जो अपनी जड़ों की ओर लौटने और नेचुरल फार्मिंग करने का फैसला कर रहे थे।

मैंने किसानों को प्रोत्साहित किया कि वे 'एक एकड़, एक मौसम' से शुरुआत करें। एक छोटे से भूखंड से भी मिलने वाले परिणाम आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और बड़े पैमाने पर इसे अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री का आलेख पढ़ने के लिए QR कोड स्कैन करें।

मैंने ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनकी जीवन यात्राएं और कुछ नया करने की प्रतिबद्धता अत्यंत प्रेरणादायी थीं।

वहां एक किसान थे जो लगभग 10 एकड़ में केले, नारियल, पपीता, काली मिर्च और हल्दी की खेती के साथ बहुस्तरीय कृषि कर रहे थे। उनके पास 60 देसी गायें, 400 बकरियां और स्थानीय पोल्ट्री थीं।

एक अन्य किसान स्थानीय धान की किस्मों जैसे मपिल्लई सांबा और करुप्पु कावुनी को संरक्षित करने में जुटे थे। वे मूल्यवर्धित उत्पादों पर काम कर रहे हैं - हेल्थ मिक्स, मुरमुरा, चॉकलेट और प्रोटीन बार जैसी चीजें तैयार करते हैं।

एक पहली पीढ़ी के स्नातक थे जो 15 एकड़ का प्राकृतिक फार्म चलाते है और 3,000 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। वे हर महीने लगभग 30 टन सब्जियां की आपूर्ति करते हैं।

कुछ लोग जो अपने स्वयं के एफपीओ चला रहे थे, उन्होंने टैपिओका किसानों का समर्थन किया और टैपिओका-आधारित उत्पादों को बायोएथेनॉल और कम्प्रेस्ड बायोगैस के लिए एक टिकाऊ कच्चे माल के रूप में बढ़ावा दे रहे थे।

कृषि नवाचार करने वालों में से एक बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल थे, जिन्होंने तटीय जिलों में 600 मछुआरों को रोजगार देते हुए एक समुद्री शैवाल-आधारित बायोफर्टिलाइजर का व्यवसाय स्थापित किया। एक अन्य ने पोषक तत्वों से भरपूर बायोएक्टिव बायोचार विकसित किया जो मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। दोनों ने दिखाया कि विज्ञान और स्थिरता कैसे सहज रूप से एक साथ चल सकते हैं।

वहां जिन लोगों से मैं मिला, वे अलग-अलग पृष्ठभूमि से थे, लेकिन एक बात समान थीः मिट्टी के स्वास्थ्य, स्थिरता, सामुदायिक उत्थान और उद्यमशीलता के प्रति पूर्ण समर्पण।

व्यापक स्तर पर, भारत ने इस क्षेत्र में सराहनीय प्रगति की है। पिछले वर्ष, भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया, जिसने पहले ही लाखों किसानों को स्थायी प्रथाओं से जोड़ा है। पूरे देश में, हजारों हेक्टेयर भूमि नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत है। निर्यात को प्रोत्साहित करने, किसान क्रेडिट कार्ड (पशुधन और मत्स्य पालन सहित) और पीएम-किसान के माध्यम से संस्थागत ऋण का उल्लेखनीय विस्तार करने जैसे सरकार के प्रयासों ने भी किसानों को प्राकृतिक खेती करने में मदद की है।

नेचुरल फार्मिंग हमारे 'श्री अन्न' यानी मिलेट्स को बढ़ावा देने के प्रयासों से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। यह भी सुखद है कि महिलाएं बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती अपना रही हैं।

पिछले कुछ दशकों में, रसायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर बढ़ती निर्भरता ने मिट्टी की उर्वरता, नमी और दीर्घकालिक स्थिरता को प्रभावित किया है। इसी दौरान खेती की लागत भी लगातार बढ़ी है। नेचुरल फार्मिंग इन चुनौतियों का सीधा समाधान करती है। पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत और मल्चिंग के प्रयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा होती है, रसायनों का प्रभाव कम होता है तथा इनपुट लागत घटती है। साथ ही जलवायु परिवर्तन और अनियमित मौसम पैटर्न के विरुद्ध मजबूती भी मिलती है।

मैंने किसानों को प्रोत्साहित किया कि वे 'एक एकड़, एक मौसम' से शुरुआत करें। एक छोटे से भूखंड से भी मिलने वाले परिणाम आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और बड़े पैमाने पर इसे अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जब पारंपरिक ज्ञान, वैज्ञानिक मान्यता और संस्थागत समर्थन एक साथ आते हैं तो नेचुरल फार्मिंग व्यवहार्य और परिवर्तनकारी बन सकती है।

मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूं कि नेचुरल फार्मिंग अपनाने पर विचार करें। आप एफपीओ से जुड़कर यह कर सकते हैं, जो सामूहिक सशक्तीकरण के मजबूत मंच बन रहे हैं। आप इस क्षेत्र से संबंधित कोई स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं।

कोयंबटूर में किसानों, विज्ञान, उद्यमिता और सामूहिक प्रयास का जो संगम देखने को मिला, वह वास्तव में प्रेरणादायक था। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर अपनी कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को अधिक उत्पादक और टिकाऊ बनाते रहेंगे। यदि आप नेचुरल फार्मिंग पर काम करने वाली किसी टीम को जानते हों तो मुझे भी अवश्य बताएं! ■

दिव्यांगजन सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2025

दिव्यांगजनों का समावेशी विकास
राष्ट्र की विकास यात्रा का अभिन्न अंग

दिव्यांगजन आज राष्ट्र की विकासधारा का न केवल हिस्सा बने हैं, बल्कि देश-दुनिया में तिरंगे का मान-सम्मान भी बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार ने बीते 11 वर्षों में दिव्यांगजनों को गरिमापूर्ण जीवन और अवसर देने के लिए सभी क्षेत्रों में सुगम्य ईको-सिस्टम खड़ा किया है। इसी का परिणाम है कि दिव्यांगजन आज अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से राष्ट्र की प्रेरणा बन रहे हैं। ऐसे ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिव्यांगजनों को वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 3 दिसंबर को प्रदान किए राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तीकरण पुरस्कार...

हार न मानें, एक कोशिश जरूर करें : पूजा गर्ग

पैरा-एथलीट पूजा गर्ग उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें दिव्यांगजन सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वह बताती हैं, "मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूं और गर्व के साथ कह सकती हूं कि इस वर्ष मुझे बेस्ट दिव्यांगजन अवॉर्ड मिला है।" 2010 में एक चोट से उन्हें गहरा आघात लगा था। वह कहती हैं, "मैं उन सभी लोगों को प्रेरित करना चाहती हूं जो किसी हादसे के बाद हिम्मत खो देते हैं। हार न मानें, एक कोशिश तो जरूर करें। मैंने कोशिश की और आज मैं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हूं। इंदौर से नाथुला तक बाइक से गई जो मेरे नाम दर्ज वर्ल्ड रिकॉर्ड है।"

लोगों को प्रेरित और मदद करना मेरी जिम्मेदारी : निपुण

जन्म से ही 'आर्थ्रोग्राइपोसिस' नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित सामाजिक कार्यकर्ता निपुण कुमार मल्होत्रा उत्कृष्टता श्रेणी में दिव्यांगजन सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 'आर्थ्रोग्राइपोसिस' ऐसी बीमारी है जिसमें हाथों और पैरों की मांसपेशियां विकसित नहीं होतीं और व्यक्ति को व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता है। निपुण कहते हैं, "डॉक्टरों ने कहा था कि मैं जीवन भर एक लकड़ी की

सुगम्य भारत अभियान के गौरवमयी 10 वर्ष

3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया था। पिछले 10 वर्षों में सुगम्य भारत अभियान ने परिवहन, भवन, और डिजिटल प्लेटफॉर्म को अधिक समावेशी बनाकर दिव्यांगजनों के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। यह सिर्फ अभियान नहीं, मानवीय संवेदना का संकल्प है।

राष्ट्रपति का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

वर्ष 2012 के पैरालंपिक में भारत को एक पदक प्राप्त हुआ था। समाज और सरकार की सजगता और सक्रियता के परिणाम-स्वरूप 2024 के पैरालंपिक खिलाड़ियों ने 29 पदक प्राप्त किए। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विश्व-स्तरीय सुविधाओं और प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन कर, सरकार द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।

– द्रौपदी मुर्मु, राष्ट्रपति

हम दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए हमेशा सम्मान, पहुंच और अवसर सुनिश्चित करने के लिए अपना वादा दोहराते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने कानून, आसान इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको साथ लेकर चलने वाली शिक्षा नीति और मददगार प्रौद्योगिकी में नवाचार के जरिए दिव्यांग कल्याण की दिशा में जरूरी कदम उठाए हैं।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

गुड़िया की तरह रहूंगा लेकिन मैंने एमबीए तक की पढ़ाई की। आज एक संस्था चलाता हूं जो दिव्यांगजनों के लिए काम करती है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं और अधिक लोगों को प्रेरित और उनकी मदद करूं।"

बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं : मो. यासीन

गायक मोहम्मद यासीन केरल राज्य पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और टेलीविजन पुरस्कार जीत चुके हैं। इन्हें दिव्यांगजन सशक्तीकरण के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। वह कहते हैं, "यह सम्मान पाकर मुझे अत्यंत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। मैं कीबोर्ड प्लेयर हूं। यहां आने से पहले मुझे थोड़ा तनाव और दबाव था लेकिन अब बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं।"

आज देश में ऐसी प्रेरणास्पद कहानियों की सूची लंबी होती जा रही है। यह परिणाम है उस सोच का जिसे दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में साझा किया था। उन्होंने कहा था, "मेरे मन में विचार आया, क्यों न हम विकलांग की जगह पर "दिव्यांग" शब्द का उपयोग करें। ये वो लोग हैं जिनके पास एक या एक से अधिक ऐसे अंग हैं, जिसमें दिव्यता और दिव्य शक्ति का संचार है। मेरे देशवासी हम विकलांग की जगह पर "दिव्यांग" शब्द को प्रचलित कर सकते हैं क्या? मैं आशा करता हूं कि इस बात को आप आगे बढ़ाएंगे।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आह्वान से देश में न केवल नया शब्द दिव्यांग सामने आया बल्कि उनके सशक्तीकरण के लिए समग्र और समावेशी दृष्टिकोण के साथ नीतिगत सुधार और योजनाएं भी साकार हुईं।

2025 के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दिव्यांगजनों के लिए किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया। उनका कहना था कि सरकार दिव्यांगजनों के समावेशन और सशक्तीकरण के लिए इको-सिस्टम को मजबूत कर रही है। उनके लिए सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास और खेल प्रशिक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कई राष्ट्रीय स्तर के संस्थान स्थापित किए गए हैं। लाखों दिव्यांगजनों को विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी किए गए हैं, जिससे उन्हें विशेष सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम में 32 दिव्यांगजनों को सम्मानित किया गया। ■

भारत में दुनिया का छठा सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर बेड़ा

भारत आज दुनिया का छठा सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर बेड़ा संचालित करता है। कुल विद्युत उत्पादन में 3 फीसदी से अधिक योगदान बना हुआ है। स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा क्षमता विस्तार के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी में हुई है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर तकनीक पर आधारित 200 मेगावाट के स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और 55 मेगावाट के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के डिजाइन और विकास की शुरुआत...

भारत सरकार देश के ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाने के लिए स्वदेशी परमाणु तकनीक पर विशेष जोर दे रही है। अब देश में पीएचडब्ल्यूआर तकनीक के बड़े आकार जैसे 700 मेगावाट के रिएक्टरों के परिपक्व होने और स्वदेशी 700 मेगावाट रिएक्टरों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से स्थापित 1,000 मेगावाट रिएक्टरों की तैनाती से परमाणु क्षमता बढ़ रही है। साथ ही निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूरा होने पर वर्ष 2031-32 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता 22.38 गीगावॉट होने की उम्मीद जताई है। सरकार ने वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावॉट तक पहंचाने के लिए 'न्यूक्लियर एनर्जी मिशन' की घोषणा भी की है। इसके साथ ही सरकार परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम करने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन करने की दिशा में बढ़ रही है।

निजी क्षेत्र के निवेश को मिलेगा प्रोत्साहन

परमाणु ऊर्जा मिशन के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए, परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन संसद में पेश किए जाएंगे। इन संशोधनों से परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

सरकार की ये रणनीति 100 गीगावाट के संकल्प की करेगी सिद्धि

- तेजी से विस्तार के लिए ग्रीन फील्ड साइट्स पर 700 मेगावाट देशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर और अधिक क्षमता वाले आयातित रिएक्टर स्थापित करना।
- ब्राउन फील्ड साइट्स के लिए 200 मेगावाट-इलेक्ट्रिक भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और 55 मेगावाट-इलेक्ट्रिक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जैसे छोटे रिएक्टरों को डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है...
  - बंद होने जा रहे जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों का पुनः उपयोग करना।
  - ऊर्जा-गहन उद्योगों के लिए कैप्टिव संयंत्र।
  - दूरदराज के क्षेत्रों के लिए ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोग।

इन रिएक्टरों की स्थापना के लिए देश में आवश्यक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और अधिकांश उपकरण भारतीय उद्योगों की निर्माण क्षमता के अंतर्गत हैं। इसमें तकनीकी मार्गदर्शन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही है। इस मिशन को अनुसंधान एवं विकास से भी समर्थन प्राप्त है। इसका उद्देश्य देशी उन्नत रिएक्टर विकसित करना है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों पर डिजाइन और विकास कार्य शुरू किया है

- भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 200 मेगावाट-इलेक्ट्रिक।
- एसएमआर 55 मेगावाट-इलैक्ट्रिक।
- 5 मेगावाट थर्मल तक उच्च तापमान गैस-कूल्ड रिएक्टर, जो हाइड्रोजन उत्पादन के लिए है।

इलेक्ट्रॉन बीम स्टरलाइजेशन... 35 देशों को चिकित्सा उपकरण निर्यात

स्वास्थ्य क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित इलेक्ट्रॉन बीम आधारित स्टरलाइजेशन सुविधा, आईएसओ मानकों के अनुरूप चिकित्सा उपकरण निर्माताओं को निरंतर ई-बीम स्टरलाइजेशन सेवाएं दे रही हैं। सितंबर 2025 में, इस सुविधा ने 1.53 करोड़ चिकित्सा उपकरणों का सफलतापूर्वक स्टरलाइजेशन किया। यहां स्टरलाइजेशन किए गए चिकित्सा उपकरण जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, पुर्तगाल, चेक गणराज्य और रूस सहित 35 से अधिक देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। वहीं उच्च-तीव्रता वाला गामा विकिरण यंत्र भी स्वास्थ्य उत्पादों के अंतिम स्टरलाइजेशन और सेवा प्रदान के लिए तैयार हो चुका है। आईएसओएमईडी 2.0 विश्व में एकमात्र उच्च-तीव्रता वाला भूमि आधारित स्थिर गामा विकिरण यंत्र है। ■

वर्ष 2025 में परमाणु ऊर्जा का विस्तार...

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर, 2025 को राजस्थान में 42,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले परमाणु ऊर्जा परियोजना (4X700 मेगावाट) की आधारशिला रखी। यह देश के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक होगा। यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण और विकसित परमाणु ऊर्जा परिदृश्य में भी भारत की स्थिति को मजबूत करेगा।
- गुजरात के काकरापार स्थित स्वदेशी 700 मेगावाट पीएचडब्ल्यू की पहली दो इकाइयों (केएपीएस- 3 और 4) को नियमित संचालन के लिए एईआरबी लाइसेंस मिल चुका है। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा परियोजना (आरएपीपी) की इकाई 7 की स्वीकृत 16 रिएक्टरों की श्रृंखला में तीसरी स्वदेशी 700 मेगावाट पीएचडब्ल्यू ने 15 अप्रैल, 2025 को वाणिज्यिक परिचालन का शुभारंभ कर दिया है।
- न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआईएल) ने अपने संपूर्ण परिचालन इतिहास में सर्वाधिक उत्पादन हासिल किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में 56,681 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन, जिससे लगभग 49 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचा जा सका।

निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी

- भारत स्मॉल रिएक्टरों की स्थापना।
- भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर का अनुसंधान एवं विकास।
- परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान एवं विकास।

भारत-रूस

विश्वास की विरासत
सहयोग का नया अध्याय

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा संकट, क्षेत्रीय संघर्ष और बदलते वैश्विक आर्थिक संतुलन के बीच भारत-रूस संबंध आज भी स्थिरता का भरोसेमंद स्तंभ है। ऐसे समय में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाली है। वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, आतंकवाद और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग न केवल द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करेगा, बल्कि संवाद को भी मजबूती प्रदान करेगा। 4 और 5 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुए अहम समझौते...

आठ दशक में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा लेकिन इन सबके बीच भी भारत-रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके दोनों देशों के संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा में इस नींव को और मजबूत करने की दिशा में चर्चा हुई। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना दोनों देशों की साझा प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए दोनों देशों के बीच वर्ष 2030 तक के लिए इकोनॉमिक

इन विषयों पर हुए समझौते

- **प्रवासन और गतिशीलता** : एक देश के नागरिकों के दूसरे देश में अस्थायी श्रम गतिविधि पर भारत सरकार और रूस सरकार के बीच समझौता।
- **स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा** : स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समझौता।
- **समुद्री सहयोग और ध्रुवीय जलक्षेत्र** : ध्रुवीय जलक्षेत्र में संचालित जहाजों के लिए विशेषज्ञों के प्रशिक्षण पर भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा रूस की सरकार के परिवहन मंत्रालय के बीच समझौता।
- **उर्वरक** : मेसर्स जेएससी यूरालकेम और मेसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. तथा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और इंडियन पोटाश लिमिटेड के बीच समझौता।
- **सीमा शुल्क एवं वाणिज्य** : भारत-रूस के बीच माल और वाहनों के संबंध में आगमन-पूर्व सूचना के आदान-प्रदान में सहयोग के लिए भारत सरकार के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा रूस की संघीय सीमा शुल्क सेवा के बीच प्रोटोकॉल।
- **शैक्षणिक सहयोग** : पुणे स्थित रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान और रूस के फेडरल स्टेट ऑटोनोमस उच्च शिक्षा संस्थान 'नेशनल टॉम्स्क स्टेट यूर्निवसिटी' के बीच वैज्ञानिक और शैक्षणिक सहयोग पर समझौता।
- **मीडिया सहयोग** : प्रसार भारती, भारत और संयुक्त स्टॉक कंपनी गजप्रोम-मीडिया होल्डिंग, रूस संघ के बीच प्रसारण पर सहयोग और सहभागिता के लिए समझौता। प्रसार भारती और द बिग एशिया मीडिया ग्रुप के बीच प्रसारण पर सहयोग और सहभागिता के लिए समझौता।

घोषणा

- भारत-रूस आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के लिए 2030 तक का कार्यक्रम।
- रूसी पक्ष का अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) में शामिल होने के लिए फ्रेमवर्क समझौता।
- रूसी नागरिकों को पारस्परिक आधार पर 30 दिनों का निःशुल्क ई-पर्यटक वीजा देने का निर्णय।
- रूसी नागरिकों को निःशुल्क समूह पर्यटक वीजा प्रदान किया जाएगा।

को-ऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनी है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश ज्यादा विविध, संतुलित और टिकाऊ बनेगा। साथ ही सहयोग के नए रास्ते भी खुलेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से दोनों एक कार में बैठ कर प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर पर पहुंचे। वहां दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में कहा कि यह यात्रा ऐसे समय में हो रही जब दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी और 15 वर्ष पहले दोनों देशों की साझेदारी को विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला था। पिछले ढाई दशक में दोनों देशों ने अपनी दूरदृष्टि से

भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य

व्यापार और आर्थिक साझेदारी

दोनों नेताओं ने रूस को भारत के निर्यात में वृद्धि, औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने में नई तकनीक और निवेश साझेदारियां बनाने पर जोर दिया। दोनों पक्षों को निवेश के संवर्धन और संरक्षण पर पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते पर बातचीत के प्रयासों को तेज करने का भी निर्देश दिया।

ऊर्जा साझेदारी

तेल उत्पाद, तेल शोधन और पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी, एलएनजी और एलपीजी से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने देशों में विभिन्न मौजूदा परियोजनाओं, भूमिगत कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी, परमाणु परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों में भारतीय और रूसी कंपनियों के बीच वर्तमान और संभावित सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया।

परिवहन और संपर्क

इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चेन्नई-व्लादिवोस्तोक (पूर्वी समुद्री) गलियारे और उत्तरी समुद्री मार्ग का समर्थन करने, संपर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता को बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक लिंक के विस्तार का निर्णय। ध्रुवीय जल में परिचालित जहाजों के लिए विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के लिए समझौता हस्ताक्षर।

रूसी सुदूर पूर्व/आर्कटिक में सहयोग

रूसी संघ के सुदूर पूर्व और आर्कटिक क्षेत्र में व्यापार और निवेश सहयोग को तेज करने का निर्णय। 2024-2029 की अवधि के लिए रूसी सुदूर पूर्व में व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में भारत-रूस सहयोग का निर्णय।

असैन्य परमाणु सहयोग और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग

ईंधन चक्र, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र और गैर-ऊर्जा अनुप्रयोगों सहित परमाणु ऊर्जा में सहयोग को व्यापक बनाने का निर्णय। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग का निर्णय। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और रूसी राज्य अंतरिक्ष निगम 'रोस्कोस्मोस' के बीच साझेदारी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग

ज्ञान के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण एवं उद्यमियों की अधिक सहभागिता को सक्षम बनाने हेतु स्टार्टअप उद्योगों के लिए सॉफ्ट सपोर्ट कार्यक्रमों को डिजाइन और क्रियान्वित करने पर सहमति।

यूएन-बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग

दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र के मुद्दों पर अपने बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद और सहयोग का जिक्र करने के साथ ही इसे और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। रूस ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपने दृढ़ समर्थन को दोहराया। रूस ने 2026 में भारत की आगामी ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए समर्थन दिया।

शैक्षणिक संबंधों को बढ़ावा

शैक्षिक संबंधों को बढ़ावा देने के प्रयासों को जारी रखने पर सहमति।

आतंकवाद का मुकाबला

दोनों पक्षों ने आतंकवाद, उग्रवाद, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, धन शोधन, आतंकवादी वित्त पोषण और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी जैसी आम चुनौतियों और खतरों से निपटने के क्षेत्र में द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे

दोनों पक्षों ने मध्य-पूर्व और पश्चिम एशिया में शांति एवं स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। संयम बरतने, नागरिकों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुपालन का आह्वान किया। ऐसी कार्रवाई से परहेज करने की आवश्यकता जताई जो स्थिति को और बिगाड़ सकती है। इस बात पर जोर दिया कि प्रमुख शक्तियों के रूप में भारत और रूस बहुध्रुवीय विश्व के साथ-साथ बहुध्रुवीय एशिया में वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए प्रयास करते रहेंगे।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

इन संबंधों को निरंतर सींचा है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का आभार व्यक्त किया।

दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक भारत-रूस आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम अपनाने का निर्णय लिया है। दोनों नेताओं ने भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच वस्तुओं पर मुक्त व्यापार समझौते के लिए संयुक्त कार्यक्रम, निवेश के संवर्धन और संरक्षण पर पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते

भारत-रूस बिजनेस फोरम

किसी भी साझेदारी की नींव, आपसी विश्वास ही होती है। भारत-रूस संबंधों की सबसे बड़ी ताकत इसी विश्वास में निहित है। यही विश्वास संयुक्त प्रयासों को दिशा और गति प्रदान करता है। यही वजह है कि भारत और रूस के बीच वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 100 बिलियन डॉलर के व्यापार का लक्ष्य समय से पहले पूरा करने का है संकल्प...

रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत से प्रेरित होकर, भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भारत-रूस बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट किया कि व्यापार के लिए सरल और विश्वसनीय व्यवस्था बनाई जा रही है। भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा शुरू हो गई है। व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार और अनुपालन में छूट दी गई है। रक्षा और अंतरिक्ष, निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए हैं। ये सब केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि मानसिकता में सुधार है।

समुद्री उत्पादों के क्षेत्र में रूस ने हाल ही में डेयरी और समुद्री उत्पादों के निर्यात हेतु पात्र भारतीय कंपनियों की सूची का विस्तार किया है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत आज किफायती और कुशल ईवी दोपहिया वाहनों के साथ-साथ सीएनजी आधारित परिवहन समाधानों में विश्व में अग्रणी है। वहीं रूस उन्नत सामग्रियों का एक प्रमुख उत्पादक है। भारत को दुनिया भर में किफायती दामों पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए 'फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड' कहा जाता है। भारत और रूस सह-नवाचार, सह-उत्पादन और सह-सृजन की एक नई यात्रा पर साथ-साथ चल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बिजनेस फोरम का लक्ष्य केवल द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना नहीं है, बल्कि वैश्विक चुनौतियों के स्थायी समाधान करना है। पीएम मोदी ने घोषणा की, 'आइए, भारत में निर्माण करें, भारत के साथ साझेदारी करें और साथ मिलकर दुनिया के लिए निर्माण करें।'

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

> *भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष शांति का है। विश्व का कल्याण शांति मार्ग पर ही है, हम सबको मिलकर शांति के राह तलाशने चाहिए। जो प्रयास चल रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा।*
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

राष्ट्रपति पुतिन को मिले उपहार

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रूसी भाषा में अनुवादित गीता की एक प्रति भेंट करते हुए कहा गीता के उपदेश विश्व भर के लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं।

- महाराष्ट्र की हस्तनिर्मित सिल्वर हॉर्स प्रतिमा राष्ट्रपति पुतिन को भेंट की गई। यह भारत की सदियों पुरानी धातु कला परंपरा का प्रतीक है। यह प्रतिमा गरिमा, वीरता और भारत-रूस साझेदारी की बढ़ती मजबूती को दर्शाती है।

- राष्ट्रपति पुतिन को आगरा का मार्बल चेस सेट भेंट किया गया। यह बारीक नक्काशी व पारंपरिक भारतीय इनले कला का सुंदर उदाहरण है। यह उपहार कौशल और रचनात्मकता को एक साथ जोड़ता है।

को तेज करने का निर्देश दिया। दोनों पक्षों ने विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए एक खुली, समावेशी, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के महत्व को रेखांकित किया। टैरिफ और गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं का समाधान निकालने पर जोर दिया। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार के निर्बाध रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं के इस्तेमाल के माध्यम से द्विपक्षीय निपटान प्रणालियों को संयुक्त रूप से विकसित करने पर सहमति जताई है। ■

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय

जनगणना बजट और कोलसेतु नीति को मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देशहित से जुड़े तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें सबसे बड़ा निर्णय वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना के लिए बजट आवंटन का है जो देश में 16वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। यह शहर और वार्ड स्तर पर प्राथमिक डेटा उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा स्रोत है। साथ ही मंत्रिमंडल ने कोलसेतु नीति और 2026 सीजन के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रस्ताव को भी दी मंजूरी...

निर्णय : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,718.24 करोड़ रुपये की लागत से भारत की जनगणना 2027 कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

प्रभाव : भारत की जनगणना 2027 में देश की समस्त जनसंख्या को शामिल किया जाएगा। यह दो चरणों में की जाएगी। पहला, गृह-सूचीकरण एवं आवास जनगणना - अप्रैल से सितंबर, 2026 और दूसरा, जनसंख्या गणना - फरवरी 2027 तक। डेटा संग्रह के लिए मोबाइल एप और निगरानी के लिए केंद्रीय पोर्टल का उपयोग किया जाएगा जो बेहतर गुणवत्ता वाला डेटा सुनिश्चित करेगा। इस राष्ट्रीय महत्व के विशाल कार्य को 30 लाख फील्ड कर्मचारी संपन्न करेंगे। इस दौरान 1.02 करोड़ मानव-दिवस रोजगार पैदा होगा।

निर्णय : आर्थिक मामलों की समिति ने कोयला लिंकेज की नीलामी के लिए कोलसेतु नीति को मंजूरी दी।

प्रभाव : यह कोलसेतु विंडो लंबी अवधि और किसी भी औद्योगिक उपयोग एवं निर्यात के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी पर आधारित आवंटन का लक्ष्य रखती है। कोई भी घरेलू खरीदार जिसे कोयले की आवश्यकता है, वह लिंकेज नीलामी में भाग ले सकता है। इस विंडो के तहत मिलने वाले कोयला लिंकेज को अपने उपभोग, निर्यात या किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही कोयला लिंकेज धारकों को अपने लिंकेज का 50% तक कोयला निर्यात करने की अनुमति होगी। लिंकेज धारक अपनी समूह कंपनियों के बीच जरूरत के अनुसार कोयले का उपयोग लचीले तरीके से कर सकेंगे।

निर्णय : 2026 सीजन के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी।

प्रभाव : इस निर्णय के तहत मिलिंग खोपरा का एमएसपी 12,027 रुपये प्रति क्विंटल जबकि बॉल खोपरा का एमएसपी 12,500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और नारियल उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उच्च एमएसपी के माध्यम से नारियल उत्पादकों को बेहतर और अधिक लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो सकेगा। साथ ही, इसका उद्देश्य किसानों को खोपरा उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है, ताकि घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नारियल उत्पादों की बढ़ती मांग की पूर्ति की जा सके।

कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस ब्रीफिंग देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

Narendra Modi
@narendramodi

जिस मंत्र और जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदेमातरम् का पुण्य स्मरण हम सबका परम सौभाग्य है।

रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India
@DefenceMinIndia

मुझे पूरा विश्वास है कि BRO, सरकार के, और इस देश के नागरिकों के भरोसे पर, ऐसे ही खरा उतरता रहेगा। "श्रमेण सर्वम् साध्यम्" की आपकी जो भावना है, वह इसी प्रकार असंभव को भी संभव बनाती रहेगी। आप इसी तरह राष्ट्र की दूरस्थ सीमाओं को भी, देश के बाकी हिस्सों से जोड़ते रहेंगे, और लोगों के दिलों में अपनी जगह इसी तरह बनाए रखेंगे: रक्षा मंत्री श्री @rajnathsingh

Amit Shah
@AmitShah

सहकारिता कल्पवृक्ष के समान है, जिसका प्रत्येक भाग समाज के काम आता है। मोदी सरकार ने सहकारिता में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देकर इसे नया जीवन दिया है।

Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

Heartiest congratulations to our Men's Junior Hockey Team for creating history at the FIH Hockey Men's Junior World Cup 2025! 🏑

Their first-ever 🥉 medal is a moment of immense pride for India. This remarkable achievement reflects their grit, passion and discipline—igniting hope and inspiring lakhs of young athletes to dream bigger and aim higher for the nation. 🇮🇳

#FIHHockeyMensJuniorWorldCup2025

Shivraj Singh Chouhan
@ChouhanShivraj

किसानों को उनकी उपज का उचित दाम देने के लिए केवल MSP ही नहीं, इस बार हमने बागवानी फसलों पर MIS योजना के अंतर्गत यदि एक निश्चित सीमा से ज्यादा रेट पट गए तो मॉडल रेट और विक्रय मूल्य का अंतर हम किसान के खाते में डालेंगे।

Shandilya Giriraj Singh
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के मिलेट्स आज वैश्विक पोषण और कृषि इनोवेशन का प्रतीक बन के उभरे हैं। 2024-25 में 180 लाख टन उत्पादन और 89,164 टन का एक्सपोर्ट इसका स्पष्ट प्रमाण है।
स्थानीय ताकत का यह वैश्विक प्रभाव दिखाता है कि भारत अब पारंपरिक कृषि को आधुनिक अवसरों में बदलते हुए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में नई राह बना रहा है।
#GharGharSwadeshi

भूली बिसरी वित्तीय संपत्ति से नए अवसर बनाने का मिल रहा अच्छा मौका : मोदी

पीएम ने की आपका पैसा, आपका अधिकार अभियान में हिस्सा लेने की अपील

देश में रेल किराया सबसे सस्ता: वैष्णव

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल जारी

पीएम मोदी से मिले इटली के उप प्रधानमंत्री, मजबूत करेंगे साझेदारी

आतंकी फंडिंग के खिलाफ साझा अभियान चलाएंगे भारत और इटली

पीएम मोदी के साथ बुधवार को मुलाकात करते इटली के उप प्रधानमंत्री तजानी।

■ अगले साल इटली जाएंगे मोदी

UNESCO की सांस्कृतिक धरोहर लिस्ट में दिवाली भी

घोषणा के साथ ही 'वंदे मातरम्' और 'भारत माता की जय' के नारे गूंज उठे

भारत की 15 परंपराएं पहले से हैं लिस्ट में

जनगणना... 11,718 करोड़ का बजट, 30 लाख कर्मी लगेंगे

जनगणना, 2027 के लिए 11,718 करोड़ रु. मंजूर किए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने जनगणना का प्रस्ताव मंजूर किया। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच मकान सूचीकरण और आवास जनगणना होगी। दूसरे चरण में लोगों की गिनती होगी। यह फरवरी 2027 में होगा। जाति से जुड़े आंकड़े भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्र होंगे। इस काम में 30

अन्य फैसले: मनरेगा- पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना

• मनरेगा का नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना होगा। काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 करने को मंजूरी। • 71 आप्रासंगिक कानूनों को निरस्त करने का विधेयक भी मंजूर। इसमें 65 संशोधन कानून शामिल हैं। • कोल सेतु मंजूर। इससे बिना एंड-यूज प्रतिबंध कोयला लिंकेज की नीलामी। 50% निर्यात, लचीला उपयोग संभव। • परमाणु ऊर्जा क्षेत्र प्राइवेट प्लेयर्स के लिए

जूनियर हॉकी टीम की जीत अनगिनत युवाओं को प्रेरित करती है : पीएम मोदी

नई दिल्ली। चेन्नई और मदुरै में हुए जूनियर हॉकी विश्वकप में भारत ने अर्जेंटीना को हराकर कांस्य पदक जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम को बधाई दी। पीएम ने लिखा, हमारी युवा और जोशीली टीम ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीता है। यह अविश्वसनीय उपलब्धि पूरे देश के अनगिनत युवाओं को प्रेरित करती है। यह भारत का विश्वकप इतिहास

ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन सिस्टम को मंजूरी... अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के पुरुष और महिला हॉकी टूर्नामेंट के क्वालिफिकेशन सिस्टम को मंजूरी दे दी है। ओलंपिक में दोनों वर्गों में 12-12 टीमें हिस्सा लेंगी। मेजबान अमेरिका के अलावा शेष 11 टीमें प्रो लीग 2025-26 और 2026-27, पांच महाद्वीपीय चैंपियनशिप और ओलंपिक क्वालिफिकेशन

राष्ट्रीय युवा दिवस - 12 जनवरी

स्वामी विवेकानंद का मार्गदर्शन
युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा

सांस्कृतिक स्वाभिमान के प्रतीक स्वामी विवेकानंद ने स्व-संस्कृति के प्रति न सिर्फ देशवासियों को जागरूक किया बल्कि विश्व को वेदांत और योग दर्शन से भी प्रभावित किया। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से उन्होंने 'नर सेवा को ही नारायण सेवा' का पर्याय बनाया। युवाओं में चरित्र निर्माण व आत्मगौरव का बीज बोकर उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने वाले स्वामी विवेकानंद का जीवन और दर्शन सभी के लिए प्रेरणापुंज है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद को उनकी जन्म-जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कृतज्ञ राष्ट्र का शत-शत नमन...

स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे युवाओं के लिए एक शाश्वत प्रेरणा हैं। साथ ही, युवा मन में जुनून और उद्देश्य को बनाए रखते हैं। हम एक मजबूत और विकसित भारत के उनके सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

न्यू इंडिया समाचार
पाक्षिक

आर.एन.आई, DELHIN/2020/78812, 1-15 जनवरी, 2026

आरएनआई DELHIN/2020/78812, दिल्ली पोस्टल लाइसेंस नंबर- DL (S)-1/3550/2023-25 डब्ल्यूपीपी संख्या- U (S)-98/2023-25, posting at BPC, Market Road, New Delhi - 110001 on 26-30 advance Fortnightly (प्रकाशन तिथि- 15 दिसंबर 2025, कुल पृष्ठ-48)

प्रधान संपादक: धीरेन्द्र ओझा, प्रधान महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक और मुद्रक: कंचन प्रसाद, महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो

कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना भवन, द्वितीय तल, नई दिल्ली- 110003 से प्रकाशित

मुद्रण: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा. लि., बी-278, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020